04 - मातृभाषा में शिक्षा का पूर्व-निर्धारित सोच के चलते विरोध

05 - लोगों को जोड़ने के लिए अहिंसक आंदोलन

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 02 जुलाई, 2025

06 - बैतूल को प्रदेश में मिली नई पहचान

07 - स्व-सहायता समूह से मिली नई राह, श्रीमती अंगूरी...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 263, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

पूरे विश्व में बढ़ता परमाणु तनाव और कमजोर IAEA

- पंकज श्रीवास्तव

ईरान, उत्तर कोरिया समेत कई देशों के बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों के बीच IAEA की निगरानी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय परमाणु संस्था इस तनाव को कम करने में नाकाम हो रही है? जून 2025 में ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। इसराइल ने ईरान के नतांज़, फोर्डो, और इस्फहान परमाणु केंद्रों पर बिना उकसावे के हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी GBU-57 बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागीं। इस युद्ध में सैकड़ों लोग मारे गए, और ईरान की परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा।

हमले का बहाना IAEA की 12 जून 2025 की रिपोर्ट थी, जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का उल्लंघन किया और उसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो 6-9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या यह रिपोर्ट युद्ध का कारण थी, या महज एक बहाना?

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक राफेल ग्रॉसी हैं। 178 सदस्य देशों वाली यह संयुक्त राष्ट्र की स्वायत्त संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करती है। इसके तीन मुख्य कार्य हैं- निरीक्षण (Safeguards): परमाणु सुविधाओं की निगरानी ताकि कोई देश परमाणु हथियार न बनाए। 2025 में IAEA ने 181 देशों में 2,114 निरीक्षण किए। सुरक्षा मानक (Safety Standards): परमाणु संयंत्रों और रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा के लिए मानक बनाना।

तकनीकी सहयोग (Technical Cooperation): स्वास्थ्य, कृषि, और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग में सहायता, जैसे कैंसर उपचार के लिए LINAC मशीनें। IAEA का संगठनात्मक ढांचा तीन मुख्य निकायों पर आधारित है- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस, और सचिवालय, जिसमें 2,560 कर्मचारी छह विभागों में काम करते हैं। इसका मुख्यालय वियना में है, साथ ही टोरंटो, टोक्यो, न्यूयॉर्क, जेनेवा और अन्य स्थानों पर कार्यालय और अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं।

1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा (6 अगस्त) और नागासाकी (9 अगस्त) पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर गिराये गये 'लिटिल बॉय' और नागासाकी पर 'फैट मैन' ने लाखों लोगों की जान ले ली। तापमान 6,000 डिग्री तक पहुंचा, शहर आग के गोले में तब्दील हो गए। कुल तीन लाख लोगों की जान गयी जिनमें एक लाख तुरंत मरे और दो लाख बाद में रेडियेशन से कैंसर से। यह वह भयावहता थी जिसने परमाणु हथियारों के खतरे को दुनिया के सामने ला दिया। विश्वयुद्ध समाप्त होने पर शीतयुद्ध का दौर शुरू हुआ और 1949 में सोवियत संघ ने कजाकिस्तान के सेमिपालाटिंस्क में अपना पहला परमाणु बम 'फर्स्ट लाइटनिंग' (RDS-1) का परीक्षण किया, जिसने अमेरिका के परमाणु एकाधिकार को तोड़ा। इसके बाद 1953 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया।

1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने "Atoms for Peace" भाषण में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत की। इसी विचार से IAEA का गठन हुआ। यह एजेंसी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी।

IAEA ने चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) जैसी दुर्घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की, रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए। लेकिन हाल के वर्षों में इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, खासकर ईरान और इसराइल के मामले में।

ईरान 1970 में NPT का सदस्य बना, और तब से IAEA उसकी परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती रही। 2015 के JCPOA समझौते के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को सीमित किया था, जिसकी निगरानी IAEA ने की। लेकिन 2018 में अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद ईरान ने संवर्धन बढ़ाया, जिससे तनाव बढ़ा।

जून 2025 के युद्ध में ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि युद्ध के कारण निरीक्षण रुक गया, जिससे स्थिति का आकलन मुश्किल हो गया। इसके जवाब में ईरानी संसद ने 22 जून 2025 को IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का विधेयक पारित किया। ईरान का तर्क है कि NPT का सदस्य होने के बावजूद उस पर हमला हुआ, जबकि उसका कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है।

ईरान के उलट, इसराइल ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपनी डिमोना परमाणु सुविधा को IAEA के निरीक्षण के लिए नहीं खोला। माना जाता है कि इसराइल के पास 90 से 200 परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने इसकी कभी पुष्टि या खंडन नहीं किया। 1960 के दशक में फ्रांस की मदद से डिमोना में रिएक्टर बनाया गया, और 1969 में अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत इसराइल के परमाणु कार्यक्रम को नजरअंदाज किया गया।

IAEA ने 2009 में इसराइल से अपनी सुविधाएं निरीक्षण के लिए खोलने की मांग की, लेकिन यह गैर-बाध्यकारी था, और इसराइल ने इसे खारिज कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दोहरा मापदंड है–ईरान जैसे NPT सदस्यों पर कड़ी निगरानी होती है, जबकि इसराइल जैसे गैर-सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

IAEA स्वयं कोई सजा नहीं दे सकती। अगर कोई देश इसका पालन नहीं करता, तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजती है, जो प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई जैसे कदम उठा सकती है। ईरान पर पहले भी कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसराइल जैसे देशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह IAEA की सीमाओं को उजागर करता है।

विश्व में लगभग 12,500 परमाणु हथियार हैं, जिनमें रूस (5,800), अमेरिका (5,200), और चीन (500) के पास सबसे ज्यादा हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के बम 15-20 किलोटन के थे, जबकि आज के बम 100 किलोटन से 1 मेगाटन तक की ताकत रखते हैं–50-100 गुना ज्यादा विनाशकारी। ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन उसके पास 400 किलोग्राम 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम होने की बात कही जाती है, जिसे युद्ध से पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह संकेत देता है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता को पुनर्जनन की कोशिश कर सकता है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा।

ईरान-इसराइल युद्ध ने IAEA की सीमाओं को उजागर किया है। इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर परमाणु हथियारों की होड़ को नहीं रोका गया, तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

आषाढ़,
तुमने ये क्या किया?
अमलतास के बदन से
पीली मोतियां छीन लीं!
ज़मीन पर बिखरी
बारिस की बूंदों में लिपटी
धूल में सनी
ये पीली मोतियां
कितनी बेबस दिख रही हैं
मेरे अमलतास!
तुम अपने मौसम में
फिर खिलना
अपने यौवन को फिर पाना
आषाढ़ नहीं आ सकता
चैत, बैसाख और जेठ में
वरना तुम्हारे यौवन को देख
मचल जाता
फिर नहीं आती
पृथ्वी के हिस्से ये बारिश
मेरे अमलतास!
मैंने
तुम्हारी अनगिनत पीली मोतियां
अनगिनत प्रेमी जोड़ों के पास
संभाल के रख दी हैं
तुम्हें मिट्टी होते
ये जोड़े नहीं देख सकते।

- भानु प्रताप सिंह

राजस्थान से यूपी-उत्तराखंड तक बारिश-बाढ़ का तांडव

- हर ओर बारिश-बाढ़ से हाहाकार, चहुंओर संकट अपार
- राजस्थान के अलवर में सड़कें डूबीं, घरों में भरा पानी
- हिमाचल में 4 जगह बादल फटा, उत्तराखंड में तबाही
- प्रयागराज में गंगा-यमुना में बाढ़, बिहार में 5 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। राजस्थान के अलवर में सोमवार को भारी बारिश के चलते सड़कों पर दो फीट तक पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा-यमुना में बाढ़ जैसे हालात हैं। घाट की तरफ 500 मीटर आगे तक पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार रात 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग लापता हैं। 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में सोमवार को कोटद्वार-बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी-मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। नदी सामान्य से चार लेवल ऊपर बह रही है। पानी घाट की ऊपरी सीढ़ियों के नजदीक आ गया है। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को लगातार अनाउंसमेंट करके चेतावनी दी जा रही है। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के धौलपुल जिले में सोमवार देर रात हुई तेज बारिश से नेशनल हाईवे-123 की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से कट गई। हाईवे से बाड़ी की ओर जाने वाला रास्ता दो हिस्सों में कट गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी के अलग-अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घरों को बारिश बाढ़ में बहने और लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। कुकलाह में कई घर और माता कश्मीरी मंदिर बह गया। बारिश को देखते हुए मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी है। हरियाणा के करनाल में सोमवार देर रात अचानक यमुना में बाढ़ आ गई। इससे रेत खनन करने के लिए खड़े तीन डंपर और एक जेसीबी मशीन डूब गई। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि ड्राइवरों को भागने मौका नहीं मिला।

हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा के नए अध्यक्ष

संगठन मंत्री का इशारा मिलते ही सीएम हाथ पकड़कर मंच पर लेकर गए

- **मथुरा में हुआ जन्म, लोकसभा सांसद भी रहे, औपचारिक ऐलान आज होगा**

भोपाल । बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल मध्यप्रदेश भाजपा के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि ऐलान बाकी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने सीएम डॉ. मोहन यादव को इशारा किया और सीएम खंडेलवाल को मंच पर ले गए। सीएम डॉ. मोहन उनके प्रस्तावक बने। खंडेलवाल पहली पंक्ति में मंत्री वीरेंद्र खटीक और गोपाल भार्गव के बीच में बैठे थे। सीएम मोहन यादव इशारा मिलते ही उनको पीठ पर हाथ रखकर मंच की ओर बढ़े। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर और पर्यवेक्षक सरोज पांडे के सामने उन्होंने नामांकन दाखिल कराया। मालवा-निमाड़ क्षेत्र से भाजपा ने सबसे ज्यादा 8 बार संगठन को नेतृत्व दिया। भाजपा के पहले प्रदेशाध्यक्ष रहे सुंदरलाल पटवा (सामान्य) मंदसौर के थे। इस पद पर वे दो बार रहे। पहली बार 1980 से 1983 तक और दूसरी बार 1986 से 1990 तक। इसके बाद रतलाम के लक्ष्मीनारायण पाण्डे (सामान्य) 1994 से 1997 तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। मालवा क्षेत्र से धार के विक्रम वर्मा (ओबीसी) 2000 से 2002 तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। इसी तरह देवास से पूर्व सीएम कैलाश जोशी (सामान्य) ने 2002 से 2005 तक संगठन का नेतृत्व किया। उज्जैन के सत्यनारायण जटिया (एससी) फरवरी 2006 से नवंबर 2006 तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। खंडवा सांसद रहे नंदकुमार सिंह चौहान (सामान्य) इस पद पर 2016 से 2018 तक रहे। ग्वालियर-चंबल से संगठन को 4 बार नेतृत्व मिला। नरेंद्र सिंह तोमर (सामान्य) को दो बार कमान सौंपी गई। पहली बार वे 2006 से 2010 तक और दूसरी बार 2012 से 2014 तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। 2014 में वो मोदी कैबिनेट में शामिल हुए। इसके बाद कमान प्रभात झा (सामान्य) को मिली, वे 2010 से 2013 तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा (सामान्य) भी चंबल से हैं। उन्हें 2020 में संगठन की कमान सौंपी गई थी। इसी तरह महाकौशल क्षेत्र से दो बार प्रदेशाध्यक्ष मिला। पहली बार शिवप्रसाद चनपुरिया (सामान्य) 1985 से 1986 से तक अध्यक्ष रहे। दूसरी बार राकेश सिंह (सामान्य) को मौका मिला। वे 2018 से 2020 तक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रहे। वर्तमान में राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। मध्य क्षेत्र से एक ही बार संगठन के नेतृत्व का मौका मिला। प्रदेश का सीएम बनने से पहले शिवराज सिंह चौहान (ओबीसी) मई 2005 से फरवरी 2006 तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ के दो नेता भी एमपी भाजपा अध्यक्ष रहे। रायगढ़ से लखीराम अग्रवाल (सामान्य) ने 1990 से 1994 तक और नंदकुमार साय (एसटी) ने 1997 से 2000 तक प्रदेश संगठन की कमान संभाली थी।

एमपी में विकसित होंगे 230 वृंदावन ग्राम

मोहन कैबिनेट का बड़ा निर्णय, योजना का किया अनुमोदन

भोपाल। गांधीनगर (गुजरात) स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का कैम्पस भोपाल में खुलेगा। इस विश्वविद्यालय के लिए मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में 10 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जर्जर 1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट ने आज वृंदावन ग्राम योजना का भी अनुमोदन कर दिया है। प्रत्येक विधानसभा (230) में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जाएगा। जिसके 27 मानक होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में बनाए गए पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन सड़कों और पुलों को सुधारने का निर्णय लिया है। 1766 पुलों के निर्माण के लिए 4572 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैम्पस भोपाल के लिए स्वीकृत हुआ है। इसके लिए 10 एकड़ जमीन आरजीपीवी कैम्पस में दी जाएगी। जब तक RRU का अपना भवन नहीं बनेगा, तब तक आरजीपीवी के भवन से संचालित किया जाएगा। जब रक्षा विश्वविद्यालय अपना कैम्पस तैयार कर लेगा, तो वहां शिफ्ट हो जाएगा। इस संस्थान के आने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रोजगार और कौशल के लिए एमपी के बच्चों को मौका मिलेगा। राज्य और राष्ट्र स्तर के मामले में मजबूती मिलेगी। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी इससे प्रगति होगी। राज्य शासन की अवधारणा है कि प्रदेश में कुछ ग्राम इस प्रकार विकसित किये जायें ताकि वे आत्मनिर्भर होकर प्रदेश के समस्त ग्रामों के लिए उदाहरण बनें तथा अन्य ग्राम इन चयनित ग्रामों से प्रेरित होकर स्वयं भी आत्मनिर्भरता और चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर हों। इन चयनित ग्रामों में विभिन्न विभागों के अन्य विकास कार्यों के साथ मुख्य रूप से गौवंशीय एवं अन्य दुधारू पशुओं के पालन, दुग्ध-उत्पादन एवं डेयरी विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य मद अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक 1766 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 4 हजार 572 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण किया जाकर बारहमासी संपर्क सुविधा प्रदान की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटिरिंग के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को समुचित निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर के परिसर (Campus) की स्थापना भोपाल में किए जाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) की स्थापना के लिए तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ 5 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), भोपाल परिसर में उपलब्ध भूमि में से 10 एकड़ भूमि को विभाग स्तर से हस्तांतरित किया जायेगा। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के स्थाई भवन का निर्माण पूर्ण होने तक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उपलब्ध भवन को अस्थायी रूप से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन किया गया। इसके स्थापित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल, विशिष्ट उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठा में वृद्धि, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35°c न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 02 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

गोली और बम रोकने से रहे, आतंकियों से डरते नहीं

● अमरनाथ तीर्थयात्रियों का दम, चुन लिया पहलगाम मार्ग

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकवादी हमले का असर इस साल अमरनाथ यात्रा पर पड़ने की आशंका थी। हालांकि, इसे दरकिनार करते हुए देश के विभिन्न भागों से सैकड़ों तीर्थयात्री पहले दिन पंजीकरण केंद्र पर कतारों में खड़े दिखाई दिए। 11वीं बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे मुंबई निवासी दिवाकर कदम ने कहा, गोली और बम हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने से नहीं रोक सकते। जम्मू रेलवे स्टेशन के निकट सरस्वती धाम पंजीकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन के पहले दिन लोगों की भीड़ देखी गई। वहां उपस्थित कई लोगों ने बढ़ती भीड़ को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को करारा जवाब बताया। आतंकियों ने 22 अप्रैल को किए गए हमले में विशेष धर्म के लोगों की पहचान करके पहलगाम में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बम बम बोले और जय बाबा बर्फानी के नारों के बीच तीर्थयात्री टोकन पाने की प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। इनमें से कई ने कहा कि वे 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहलगाम मार्ग से अमरनाथ की तीर्थयात्रा कर रहे हैं। दिवाकर कदम ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं। हमारे 26 सदस्यों का समूह बेहद खुश है। हम अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें कोई डर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अमरनाथ यात्रा के लिए देशभर के लोगों का उत्साह कम नहीं हो सकता। हर कोई आएगा और दर्शन करेगा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की 38 दिवसीय तीर्थयात्रा तीन जुलाई को दो मार्गों से शुरू होगी। इसमें अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम मार्ग है।

अग्नि-5 मिसाइल होगी और घातक, बंकर भेदने में सक्षम

● डीआरडीओ 2 वर्जन पर कर रहा है काम, जबरदस्त तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत बंकर-भेदी क्षमता वाली नई हाई पावर की मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जो बेहद सुरक्षित माने जाने वाले भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होंगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन अग्नि-5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के नए वर्जन पर काम कर रहा है। यह मिसाइल कंक्रीट की परतों के नीचे 80 से 100 मीटर तक आसानी से पहुंच सकती है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु स्थलों को भारी बंकर-भेदी बमों का इस्तेमाल करके ध्वस्त कर दिया था। कहा जा रहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ भी कुछ ऐसी ही ताकत हासिल करना चाहता है। मौजूदा अग्नि-5 मिसाइल की रेंज 5 हजार किलोमीटर से अधिक है।

अब पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसका लाभ दो चरण में मिलेगा। पहले चरण में में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे। किस्त नौकरी लगने के छठे और 12वीं महीने में मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में 3000 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस योजना में कुल 1.07 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

कृषि उत्पादों पर अमरीका के आगे नहीं झुकेगा भारत

● राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाने की तैयारी, 8 दिन बचे

वाशिंगटन (एजेंसी)। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत फिलहाल गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्धारित 8 जुलाई की समयसीमा भी तेजी से नजदीक आ रही है। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस तारीख के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26 फीसदी जवाबी टैरिफ लागू करने की संभावना है।

भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए रुका हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हालांकि, ट्रंप यह स्पष्ट कर चुके हैं कि टैरिफ सस्पेंशन को और आगे बढ़ाने की संभावना बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, सेब, और अन्य फलों एवं मेवों पर आयात शुल्क कम करे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस मांग को मानने में हिचक रही है, क्योंकि इन उत्पादों से देश के लाखों छोटे किसान जुड़े हुए हैं। राजनीतिक रूप से भी कृषि क्षेत्र में रियायत देना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। मोदी सरकार का कहना है कि इन उत्पादों पर निर्भर छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा, डेयरी और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भारत का रुख सख्त है, क्योंकि यह किसानों की आजीविका और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताओं से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी आरक्षण नीति लागू हुई

● सभी कर्मचारियों को प्रमोशन और सीधी भर्ती में मिलेगा फायदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी के लिए स्टाफ की भर्तियों में आरक्षण होगा। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। यह बदलाव मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के कार्यकाल में हुआ है। वे अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे सीजेआई हैं। 23 जून से यह नियम लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 24 जून को एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी। शीर्ष अदालत ने अपने कर्मचारियों को बताया कि आरक्षण का नियम 23 जून से लागू हो गया है। इसका आदेश का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को आरक्षण लिस्ट में कोई गलती दिखती है, तो वे भर्ती विभाग के रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। यह आरक्षण अलग-अलग पदों के लिए है। जैसे कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चेंबर अटेंडेंट।

तेलंगाना विस्फोट में बढ़ गई मृतकों की संख्या

● बढ़कर 36 पहुंची, मलबे में दबे मिले कई शव

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के पाशमायलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलबे को हटाने के दौरान कई शव मिले। जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने बताया, 'मलबे से अब तक 31 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 5 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बचाव अभियान का अंतिम चरण अभी भी जारी है।' मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा ने बताया। यह घातक हादसा सोमवार को हुआ, जिसके पीछे संदिग्ध कारण रासायनिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फार्मास्युटिकल कंपनी है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने बताया कि जब विस्फोट हुआ तब संयंत्र में लगभग 90 लोग काम कर रहे थे। विस्फोट कथित तौर पर संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुआ, जिससे आग भी लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कुछ श्रमिक लगभग 100 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरे।

कर्नाटक में डीके की हार, लॉबिंग चली गई बेकार

● बगल में बिठाकर बोले सुरजेवाला-सीएम नहीं बदलेगा

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में बीते कई दिनों से डीके शिवकुमार के समर्थक मांग कर रहे थे कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। सिद्धारमैया की जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें बगल में बिठाकर दावा खारिज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि आपका सवाल है कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है तो मेरा जवाब ना में है। सुरजेवाला ने कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व बदल रहा है। इस पर मेरी एक ही जवाब है कि नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों की ओर से लीडरशिप चेंज की मांग की गई है। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं अपने विधायकों को सलाह देता हूं कि यदि उन्हें कोई परेशानी है तो फिर मसले को मीडिया में उठाने की बजाय पार्टी फोरम पर बात करें।

सऊदी अरब के विद्यार्थियों ने किया हिंदी में काव्य पाठ

भोपाल। विश्व रंग फाउंडेशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र एवं प्रवासी भारतीय शोध केंद्र रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा सऊदी अरब की विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य पाठ का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के रियाद ,खोबर ,जिद्दाह, जुबैल, दमाम आदि शहरों के पांच से बारह वर्ष के 15 विद्यार्थियों ने हिंदी में अत्यंत जोशीले अंदाज में काव्य की पाठ किया। विद्यार्थियों ने स्वरचित के अलावा भारत के प्रमुख कवियों रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी , अटल बिहारी वाजपेई आदि की रचनाएं भी सुनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किंग सऊद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र मेहता रहे और अध्यक्षता रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने की। प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉ जवाहर कर्णावट ने विश्व रंग फाउंडेशन की गतिविधियों का परिचय दिया। कार्यक्रम का संयोजन सऊदी अरब की हिंदी एवं गुजराती लेखिका श्रीमती आरती परीख ने किया। अंत में विश्व रंग के सचिव संजय सिंह राठौड़ ने आभार माना। इस कार्यक्रम में देश-विदेश के अनेक श्रोता बड़ी संख्या में शामिल हुए।

इंडियन नेवी ने फिर दिखाया जलवा, बना हुआ है रुतबा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन नेवी ने उत्तरी अरब सागर में जोखिमभरी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शिप पर लगी आग को काबू में किया। इसमें सवार 14 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान बचाई। इस टैंकर पर पालाउ का झंडा लगा हुआ था। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि 29 जून की सुबह मिशन पर तैनात इंडियन के शिप आईएनएस टबर को इस टैंकर से आपातकालीन मदद का कॉल मिला। शिप ने बताया कि उसके इंजन रूम में भयंकर आग लग गई है।

आरसीबी ही जिम्मेदार पुलिस नहीं है भगवान

● बेंगलुरु भगदड़ पर आ गई ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट

● कहा-पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं

बेंगलुरु (एजेंसी)। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ केस में ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक 14 वर्षीय बच्ची भी शामिल थी। आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि आरसीबी ने पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिसकर्मी भी इंसान हैं, उनके पास अलादीन का चिराग थोड़े है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरसीबी ने सोशल मीडिया पर बिना पुलिस की अनुमति के विजय जुलूस का आमंत्रण पोस्ट कर दिया, जिससे भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस के पास सुरक्षा इंतजाम के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया,आरसीबी ने पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली।

व्यापार चर्चा और भारत-पाकिस्तान सीजफायर में संबंध नहीं

● जयशंकर बोले-अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पीएम से जब बात हुई, मैं भी उसी कमरे में था

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका दौर पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी चर्चा और भारत-पाकिस्तान सीजफायर के बीच कोई संबंध नहीं है। न्यूजवीक मेगजीन के सीईओ देव प्रसाद के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। जयशंकर ने कहा- 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। मैं भी उस दौरान उसी कमरे में था।

वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है। पीएम मोदी ने इसकी परवाह न करते हुए कहा था- हमले का जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा- अगली सुबह (10 मई) अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पीएम से संपर्ककिया। कहा- पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से संपर्क किया और सीजफायर की रिक्वेस्ट की थी। दरअसल, 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की सबसे पहली सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी थी। ट्रम्प ने कई मौके पर कहा है कि भारत-पाकिस्तान को व्यापार न करने की धमकी दी थी, इसके बाद दोनों देश सीजफायर के लिए माने। जयशंकर ने कहा- घटनाक्रम उस तरह से नहीं हुआ था। कूटनीति और व्यापार संबंधी चर्चा पूरी तरह से अलग हैं। मुझे लगता है कि व्यापार से जुड़े लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, जैसे- नंबर, लाइनों, प्रोडक्ट्स और व्यापार समझौता। वे सभी इसके प्रोफेशनल हैं और फोकस्ड हैं। जयशंकर ने कहा- भारत का रुख साफ है आतंकवादियों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। अब उन्हें प्रॉक्सी को तौर पर नहीं देखा जाएगा। आतंकियों को पालने वाली सरकारों को नहीं बख्शेंगे। चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सोचा समझा आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना था। यह हमला पर्यटन पर हमला था, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डरें, पर्यटक न आएं और घाटी का आर्थिक ढांचा टूट जाए।

राजा पर आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस करेंगे

इंदौर। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से पांच आरोपी जेल की सलाखों में है, जबकि तीन आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं। इसी बीच, कुछ दिन पहले कथित युवती का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें युवती ने राजा पर आरोप लगाए थे कि उसके पांच साल से संबंध थे। सचिन पर भी युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही थी। मामले में राजा के भाई विपिन ने कहा कि युवती जो आरोप लगा रही है, उसके सबूत पेश करे। मेरे भाई को बदनाम कर रही है। वे शीघ्र ही युवती के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराएंगे।

पुलिस चौकी के पास चोरी का प्रयास

इंदौर। पुलिस की निष्क्रियता के चलते शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने तिलक नगर पुलिस चौकी के पास दुकानों के ताले चटकाकर वारदात का प्रयास किया। अन्य स्थानों पर भी घटनाएं हुई। घटना से क्षेत्र में रोष है। सोमवार सुबह तिलक नगर थाना क्षेत्र में व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे तो घटना का पता चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी गई। चोरों ने सब्जीमंडी वाली गली में दुकानों के ताले तोड़े थे। पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है। इसी प्रकार, अनूप नगर में रहने वाली प्रतिभा नांदेचा ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि घर के बाहर उनकी कार क्रमांक एमपी-09-सीटी-9175 खड़ी थी, जिसे अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। फरियादी के मुताबिक, घटना रविवार को दोपहर ढाई बजे के आसपास हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर चोर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। छत्रीपुरा थाने में फरियादी सतीशचंद्र बाबूलाल आगार निवासी सोमानी नगर ने शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि बियाबानी स्थित प्रेम कुमारी अस्पताल के सामने जगन्नाथ रथयात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान उनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के अलावा 10 हजार नगदी रखे हुए थे। उल्लेखनीय है कि यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात था, इसके बावजूद बदमाश ने चोरी कर ली।

पति के दोस्त ने छेड़छाड़ की

इंदौर। पति के दोस्त ने आजाद नगर में रहने वाली महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने बताया कि रविवार रात जब उसके पति और देवर काम से बाहर गए थे और वह घर पर अकेली थी। रविवार रात 10 बजे पति का दोस्त अरविन्द घर आया और पति के बारे में पूछताछ की। जब मैंने बताया कि पति घर पर नहीं हैं तो वह चला गया, लेकिन महिला जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि अरविन्द फिर से घर में घुस आया था। आरोप है कि अरविन्द ने महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचा और गिरा दिया। इसके बाद उसने कपड़े फाड़ने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर वह मौके से भाग निकला।महिला ने पति के लौटने पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

डॉक्टर और सीए का सम्मान होगा

इंदौर। स्वच्छता में देशभर में अग्रणी इंदौर अब सेवा और समर्पण के प्रतीक प्रोफेशनल्स का भी सम्मान करेगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए डे के अवसर पर इंदौर नगर निगम द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में होने वाले इस आयोजन में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। महापौर भार्गव ने कहा कि डॉक्टर्स मानवता की सेवा में अग्रणी हैं और सीए देश की आर्थिक संरचना की रीढ़। दोनों ही समाज की नींव को मजबूत करते हैं। नगर निगम की यह पहल सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मान देने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास माना जा रहा है।

बाइक फिसलने से पत्नी की मौत

इंदौर। तेज गति से जा रही बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बाइक पर एक दंपत्ति जा रहे थे। अचानक दोनों गिर गए। दंपत्ति संभलते इसके पहले ही पीछे से आ रहे भारवाहक वाहन में महिला को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, पति को गंभीर चोट आई है। हादसा तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बायपास स्थित होटल एम्बिएंस के सामने के सामने हुआ था। महिला के पति कथावाचक हैं। दोनों अपनी बेटी से मिलकर घर लौट रहे थे। हादसे में 38 वर्षीय आशा पति किशोर शर्मा की मौत हो गई। घायल के भाई राजेश के अनुसार किशोर की बेटी कन्नू छोटे भाई संजय के पास मूसाखेड़ी में रहती है। दंपत्ति दोपहर को कन्नू से मिलने गए थे। दोनों रात में घर ग्राम दतोदा आ रहे थे। मृतक की तीन लड़की और एक लड़का है। टक्कर मारने वाला वाहन अज्ञात है। घटनास्थल पर कैमरे में भी नहीं है। पुलिस अन्य जगहों के फुटेज निकाल रही है।

चांदबाई छाजेड़ का संथारे सहित देवलोक गमन

खाचरौद। चांदबाई धर्मपत्नी स्व.माणकलाल छाजेड़ द्वारा 28 जून को सल्लेखना व्रत अंगीकार किया गया था। संथारा व्रत के दौरान विभिन्न नगरों से आकर लोगों ने आपके दर्शन किए। 30 जून को रात्रि 8 बजे जिनवाणी श्रवण करते हुए वे तीसरा मनोरथ पूर्ण कर मोक्ष लक्ष्य की ओर महाप्रयाण कर गई। खाचरौद नगर में 1 जुलाई को खब्बावास स्थित निवास स्थान से आपकी डोल यात्रा निकाली गई। जिसमें भारी की संख्या में महिला पुरुषों बच्चों ने धार्मिक जयकारों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। डोल यात्रा में रतलाम, जावरा, लिमडी,भाटपचलाना,सैलाना, नागदा,महिदपुर,दाहोद, झाबुआ, मेघनगर सहित विभिन्न नगरों के धर्मालुजन सम्मिलित हुए। चबूतरा चौराहे पर ऋतुराज बुड़ावन वाला, नरेंद्र गुरु, अजीत भटेवरा,बबलू दलाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शांति वन में उनकी पार्थिव देह को उनके पुत्र अशोक, सुनील, अनिल छाजेड़ के साथ ही स्थानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष मनोहर लाल भटेवरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। शांति वन में शोकसभा का आयोजन कर उनकी आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना की गई।

फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर से किराएदार का झूठ पकड़ा, कोर्ट में केस ख़ारिज

इंदौर। राजवाड़ा क्षेत्र स्थित मौके की दुकान की किराएदारी के मामले में जिला न्यायालय ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। किराएदार ने भाड़ा चिट्ठी की फोटोकापी पर नीले पेन से हस्ताक्षर कर कोर्ट में पेश किए, जिसे कोर्ट ने मान्य नहीं कर याचिका खारिज कर दी। एडवोकेट कृष्णकुमार कुन्हारे के अनुसार, दुकान मालिक निजाम एहमद ने बताया कि उनकी मां आयशा बी के विरुद्ध व्यापारी ने स्वयं को अक्टूबर 2020 में किराएदार बताते हुए केस जिला कोर्ट में पेश किया था। इसमें व्यापारी ने 3 अक्टूबर 2020 को सड़क चौड़ीकरण का बहाना कर दुकान का आंशिक भाग तोड़ दिया था।

रतलाम से जब्त ज्वेलरी और दस्तावेज की राजा के बड़े भाई ने शिनाख्त की

इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है और रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच शिलांग से आई एसआईटी टीम ने रतलाम से राजा और सोनम रघुवंशी की गोल्ड ज्वेलरी जब्त की। इसकी शिनाख्त के लिए राजा के भाई विपिन को रविवार देर रात क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया। पुलिस ने ज्वेलरी दिखाकर एक घंटे तक बातचीत की। बताया गया कि सोमवार को भी शिलांग पुलिस ने विपिन से पूछताछ की। लेकिन, विपिन के मुताबिक, शादी के समय सोनम को 16 लाख की ज्वेलरी दी गई थी, वो कहां है! प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स ने रतलाम में अपने ससुराल में ज्वेलरी छुपाई थी। पुलिस ने सोने की चैन, अंगूठी, मंगलसूत्र, पाजेब और बिछिया बरामद की। ज्वेलरी के साथ लैपटॉप और डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए।

शिलांग ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक ने भी इसकी पुष्टि की है। दरअसल, एसआईटी को सूचना मिली थी कि आरोपियों ने रतलाम में आभूषण बेचे थे। इसकी तलाश में शिलांग पुलिस इंदौर से शिलोम जेम्स के साथ उसकी पत्नी और साली को लेकर उसके ससुराल मनोज गुप्ता के घर पहुंची। शिलोम की पत्नी के घर से छानबीन के दौरान एक बैग जब्त किया गया, जो किचन में छुपाकर रखा गया था। बैग को जब्त कर इसमें रखे सामान का पंचनामा बनाया गया। इसके बाद रतलाम से आरोपी शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के लिए रवाना आए।

राजा हत्याकांड में मिला बड़ा सबूत, शिलांग पुलिस ने बहुत कुछ जाना

राजा के परिवार के दिए गहने नहीं मिले – राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने कहा कि सोनम को उनके परिवार ने विवाह के दौरान करीब 16 लाख रुपए के जेवरात तोहफे में दिए थे। विपिन रघुवंशी ने यह दावा शिलांग पुलिस ने रतलाम से रविवार को अहम सबूत के तौर पर कुछ जेवरात, लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद किए है। विपिन ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने शिलांग पुलिस को करीब 16 लाख रुपए मूल्य वाले सोने और चांदी के उन जेवरात की तस्वीरें सौंपी, जो राजा और सोनम के विवाह के दौरान उनके परिवार ने अपनी बहू को भेंट में दिए थे। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने बताया कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस टीम ने मुझसे राजा और सोनम की शादी से जुड़े जेवरात की तस्वीरें मांगीं है।

शिलोम पर सबूत मिटाने का आरोप– बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने शनिवार (21 जून) को प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को हिरासत में लिया था। इसके बाद रविवार (22 जून) को शिलांग पुलिस अशोक नगर के शाडोरा थाना क्षेत्र के मदागन गांव से बल्ला उर्फ बलवीर (गार्ड) को गिरफ्तार किया। शिलोम और गार्ड बलवीर पर सबूत मिटाने का आरोप है। लोकेंद्र के कहने पर ही शिलोम जेम्स ने काला बैग जलाया था। जिसमें देशी पिस्टल, पांच लाख रुपए, राजा की चेन, मोबाइल, सोनम के कपड़े और आभूषण रखे गए थे। एसआईटी टीम ने 3 से 10 जून तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें शिलोम अपनी कार में बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिया था।

अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार– सोनम ने आपने आशिक राज कुशवाह (21) के साथ राजा की हत्या का प्लान बनाया था। राज ने भी अपने तीन दोस्तों आनंद सिंह कुर्मी (23), आकाश राजपूत (19) और विशाल सिंह चौहान (22) को राजा की हत्या के लिए भेज दिया था। इस हत्याकांड मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसमें मर्डर केस की मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाह, आनंद सिंह कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान हैं। इसके अलावा इंदौर का प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, चौकीदार बलबीर सिंह और लोकेंद्र सिंह तोमर को भी गिरफ्तार किया है।

शिलांग पुलिस शिलोम के ससुर से पूछताछ करेगी, शिलोम की पत्नी से पूछताछ की गई

इंदौर। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या के मामले में गिरफ्तार ब्रोकर शिलोम से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। टीम ने रविवार को शिलोम के ससुराल रतलाम से बैग, लैपटॉप, पेन ड्राइव आदि जब्त किया था। लैपटॉप से पुलिस को अहम सुराग मिल सकते हैं। अब एसआईटी की टीम शिलोम के ससुर मनोज गुप्ता से भी पूछताछ करने वाली है। बताया गया कि सामग्री को छिपाने में मनोज की भूमिका भी है। जिस दिन से शिलोम को पुलिस ने पकड़ा, वह घर से फरार चल रहा है। ससुर मनोज के फरार होने से शिलांग पुलिस का शक और गहरा गया है। राजा हत्याकांड के बाद शिलोम कुछ लोगों के संपर्क में था। वह मोबाइल पर लगातार उनसे बात कर रहा था। एसआईटी उनकी जानकारी निकालना चाहती है। फिर उनसे भी सवाल-जवाब किए जाएंगे। टीम जब शिलोम के ससुराल पहुंची, तो यहां उसके ससुर मनोज गुप्ता नहीं मिले। टीम ने आसपास वालों से बात की तो पता लगा कि उन्हें मनोज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनोज गुप्ता म्यूचुअल फंड का काम करता है। शिलोम जेम्स भी मूल रूप से रतलाम का रहने वाला है।

इंदौर-देवास हाईवे पर हाईकोर्ट सख्त, 68 करोड़ का ठेका मिलने के बावजूद कार्य अभी भी अधूरा

एनएचएआई और ठेका कंपनी को एक सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर

इंदौर। इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और ठेका प्राप्त कंपनी डीजी बहिलकर को एक सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया। यह उल्लेखनीय है की एनएचएआई द्वारा जुलाई 2023 में एक एग्रीमेंट के तहत 68 करोड़ की लागत से दिए गए मेंटेनेंस व इम्प्रूवमेंट का काम डीजी बहिलकर कंपनी को सौंपा गया था। इस परियोजना में सर्विस रोड का निर्माण, सडक़ मरम्मत और अन्य संरचनात्मक सुधार शामिल थे। हालांकि, लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो सर्विस रोड तैयार हुई है और न सडक़ की हालत में कोई विशेष सुधार दिखाई दे रहा है। सबसे गंभीर बात यह कि इस क्षतिग्रस्त राजमार्ग के चलते अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद एनएचएआई की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब या कार्रवाई सामने नहीं आई। न्यायालय ने इस निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की ओर

से न तो संतोषजनक उत्तर दिया गया है और न यह बताया गया कि जवाब कब तक प्रस्तुत किया जाएगा। याचिकाकर्ता तनिष्क पटेल स्वयं अदालत में उपस्थित हुए, जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत किशोर ने पैरवी की। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि शासन द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है कि 14 नवम्बर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा देवास-राऊ रोड की मरम्मत कार्य चार सप्ताह में पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। किंतु, आदेश का पालन न किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि यह अदालती आदेश की अवमानना है। एनएचएआई की ओर से सुनवाई के दौरान यह तर्क बार-बार दोहराया गया कि कुछ संबंधित पक्षों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अदालत ने इस रुख को सुनवाई टालने की कोशिश मानते हुए गंभीरता से लिया और कहा कि यह रवैया न केवल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही को भी दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि एनएचएआई को समयबद्ध उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाए और साथ ही ठेका कंपनी की जवाबदेही भी निर्धारित की जाए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।

पुलिस ने की डी-मार्ट में बम थ्रेट मॉक ड्रिल

इंदौर। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। इस क्रम में पुलिस की सुरक्षा शाखा और बीडीडीएस टीम ने रेती मंडी के पास स्थित डी मार्ट में मॉक ड्रिल कर बम थ्रेट की स्थिति का जीवंत अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) राजकुमार सराफ और बीडीडीएस प्रभारी खालिद मुश्ताक ने किया। टीम ने डी मार्ट के सुरक्षा स्टाफ के साथ मिलकर यह अभ्यास किया कि किसी लावारिस या विस्फोटक सामग्री मिलने पर किस प्रकार त्वरित और सुरक्षित कार्रवाई की जाए।

ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ऐसी स्थिति में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ ही,स्टाफ को जरूरी सावधानियों और आपदा प्रबंधन के उपायों की जानकारी दी गई।

रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली चार जोड़ी ट्रेन पुनः विस्तारित की गई

इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के फेरों में पुनः विस्तार किया गया है। विस्तारित की गई ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है।

- वलसाड-खातीपुरा-वलसाड स्पेशल (गाड़ी संख्या 09007) वलसाड-खातीपुरा स्पेशल 3 जुलाई से 25 सितंबर तक वलसाड से प्रति गुरुवार को तथा गाड़ी संख्या 09008 खातीपुरा-वलसाड स्पेशल 4 जुलाई से 26 सितंबर तक खातीपुरा से प्रति शुक्रवार को चलेगी।

- डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)-पटना डॉ अम्बेडकर नगर स्पेशल गाड़ी (संख्या 09343) डॉ अम्बेडकर नगर-पटना स्पेशल 3 से 31 जुलाई डॉ अम्बेडकर नगर से प्रति गुरुवार को तथा गाड़ी संख्या

09344 पटना डॉ अम्बेडकर नगर स्पेशल 4 जुलाई से 1 अगस्त तक पटना से प्रति शुक्रवार को चलेगी।

- वडोदरा-मऊ-वडोदरा स्पेशल गाड़ी (संख्या 09195) वडोदरा-मऊ स्पेशल 7 से 28 जुलाई तक वडोदरा से प्रति सोमवार को तथा गाड़ी संख?या 09196 मऊ-वडोदरा स्पेशल 8 से 29 जुलाई तक मऊ से प्रति मंगलवार को चलेगी।

- बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल गाड़ी (संख्या 09043) बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी स्पेशल 6 से 27 जुलाई तक बांद्रा टर्मिनस से प्रति रविवार को तथा गाड़ी संख्या 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 7 से 28 जुलाई तक चलेगी।

निःशुल्क प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शिविर में 11 हजार से अधिक की जांच हुई

संभाग आयुक्त की पहल पर एक माह में 13 स्वास्थ्य शिविर हुए

इंदौर। संभाग आयुक्त दीपक सिंह की पहल पर गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए इंदौर में स्वास्थ्य विभाग और अरविंदो मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कार्यक्रम के तहत जून माह में 13 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इसमें 11 हजार से अधिक लोगों की जांच की गई। इसमें हार्ट, लिवर, कैंसर, टीबी, हड्डी एवं गठिया रोग, दंत रोग एवं नेत्र रोगों आदि से जुड़ी अत्याधुनिक जाँचें हुई। इन जांचों में मुख्य रूप से कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, टीबी चेस्ट स्क्रीनिंग, गाइनिक स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट लंप स्क्रीनिंग, ईसीजी, फाइब्रोस्कैन, चेस्ट एक्सरे, ईको, यूएसजी, मैमोग्राफी, कॉल्पोस्कोपी, पेप स्मियर, आर्थो, ऑप्टेल चेकअप, डेंटल चेकअप, एचबी, आरबीएस, एसजीपीटी, एसजीओटी, लिपिड प्रोफाइल और जनरल मेडिसिन जाँचें शामिल थी। संभाग आयुक्त की पहल पर आयोजित किए गए इन प्रिवेंटिव

हेल्थ चेकअप कैंप में जाँचों के दौरान ऐसे मरीजों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया जो फिलहाल किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं अथवा जिनके निकट भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका है। ऐसे मरीजों में हार्ट, कैंसर, लिवर, ऑर्थो आदि के मरीज भी शामिल हैं। इन सभी मरीजों को समुचित उपचार हेतु निर्देशित कर उन्हें जरूरी चिकित्सीय सलाह एवं जानकारियां प्रदान की गईं। चुनिंदा मरीजों का इलाज श्री अरबिंदो अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है। इलाज के दौरान उन्हें आयुष्मान एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।

समीक्षा में होगी शिविरों की रूपरेखा

डॉ आदित्य चौरसिया ने बताया कि गैर-संचारी रोगों की जांच एवं इलाज के तहत 13वाँ कैंप सोमवार को गांधी हॉल में आयोजित किया गया। इसमें इंदौर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं विशेषज्ञ मौजूद रहे। इंदौर जोन के इन स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा के पश्चात संभाग के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के शिविरों की रूपरेखा तय की जाएगी। इस संबंध में गांधी हॉल शिविर में निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ माधव हसानी से भी चर्चा की गई है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सिलसिला सन्मति स्कूल से शुरू हुआ जो बाल विनय मंदिर, सीएम राइज स्कूल नंदानगर, शासकीय कन्या विद्यालय अहिल्या नगर, कनकेश्वरी स्कूल नंदानगर, गुजराती स्कूल, जिला अस्पताल धार रोड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाणगंगा, यूपीएचसी गुमाश्ता नगर, पीएचसी स्कूल बिचौली हप्सी, खजराना गणेश मंदिर, यूपीएचसी खजराना और गांधी हॉल तक जारी रहा।

जनसंपर्क के संयुक्त संचालक डॉ. आरआर पटेल को विदाई

मीडिया संगठनों व अधिकारियों ने योगदान सराहा

इंदौर। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉ आरआर पटेल को भोपाल स्थानांतरित होने पर सोमवार को एक गरिमामय समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉ पटेल के कार्यों की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत इंदौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वूमन्स प्रेस क्लब की अध्यक्ष शीतल राय सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने डॉ पटेल के प्रशासन और प्रेस के बीच सेतु के रूप में निभाई गई भूमिका को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्होंने कुशल समन्वय और दक्ष प्रबंधन

से विभागीय कार्यों को उत्कृष्ट रूप से निभाया। डॉ पटेल की कर्मठता, लगनशीलता और सकारात्मक सोच प्रशंसनीय रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. पटेल राज्य स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को उसी दक्षता से निभाएंगे जैसे इंदौर में निभाया। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि डॉ पटेल एक विलक्षण अधिकारी हैं, जिन्होंने मीडिया और प्रशासन के बीच सशक्त समन्वय स्थापित कर इंदौर को नई पहचान दी। वे सदैव सहजता, संवेदनशीलता और कुशल संवाद के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने डॉ. पटेल के प्रशासनिक योगदान, मीडिया से उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों और जनसंपर्क क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की।

संपादकीय

हिंदी : आदेश वापसी का दांव

महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा बन चुके स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले के तहत पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के आदेश को राज्य की फडणवीस सरकार ने विपक्ष के दबाव में वापस जरूर ले लिया है, लेकिन जिस तरह से यह वापस लिया गया है, वह भी नया सियासी दांव हो सकता है। इसका पहला असर तो राज्य में करीब आ रहे दो धुर विरोधी ठाकरे बंधुओं के बीच मन मिलाप अब होगा या नहीं कहना मुश्किल है। दूसरे, मुख्यमंत्री फडणवीस ने आदेश वापस लेकर विपक्ष के हाथों से वो मुद्दा छीन लिया है, जो राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकता है। चूंकि आदेश ही वापस हो गया तो रस्म अदायगी के तौर पर दोनों ठाकरे बंधुओं ने 5 जुलाई को विजय दिवस रैली निकालने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपने झंडे लाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कोई भी ऐसा संदेश नहीं दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सचमुच करीब आती दिखाई दे। शिवसेना और अन्य कुछ संगठनों ने त्रिभाषा फार्मूले को राज्य की जनता पर हिंदी थोपने के रूप में प्रचारित किया। उसने राज्यभर में हिंदी लागू करने के आदेश की प्रतियां जलाने का ऐलान कर दिया। जिसमें राज्य सरकार ने यह आदेश नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बच्चों को पहली कक्षा से तीन भाषाएं, जिनमें पहली मातृ भाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया था। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी पढ़ाई तो जाती है, लेकिन वह अनिवार्य नहीं है। इस आदेश को राजनीतिक तौर पर भाजपा द्वारा महाराष्ट्र पर मोदी सरकार द्वारा हिंदी थोपने के रूप में प्रचारित किया गया। इसको लेकर कई विपक्षी दल और मराठी साहित्यिक भी एकजुट होने लगे। इस लामबंदी के बाद सत्तारूढ़ महायुति के प्रमुख घटक राकांपा के नेता और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने भी तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता पर सवाल उठा दिए। इससे राज्य में मराठी भाषी बनाम हिंदी भाषी गोलबंदी होने लगी। इसका प्रभाव राज्य में जल्द होने वाले मुंबई महानगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में हो सकता था। यही कारण है कि देवेन्द्र फडणवीस से यह मुद्दा विपक्ष से छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कैबिनेट बैठक के बाद सहयाद्री गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमने कैबिनेट में तीन-भाषा नीति पर विस्तार से चर्चा की और 16 अप्रैल और 17 जून 2025 को जारी किए गए जीआर को रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि डॉ नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि किस कक्षा से तीन-भाषा नीति लागू की जानी चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए 'इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी।' इसके पहले उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि स्कूलों में हिंदी पढ़ना वैकल्पिक होगा, न कि अनिवार्य। फडणवीस ने इसे विपक्ष की 'घिनौनी राजनीति' पर निराशा व्यक्त की और बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने डॉ. रघुनाथ माशेलकर की तीन-भाषा सूत्र रिपोर्ट को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया था। फडणवीस ने कहा कि यह ठाकरे की सरकार थी, जिसे तत्कालीन कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी का समर्थन प्राप्त था, जिसने अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। अभी हालांकि आदेश वापस ले लिया गया है, लेकिन यह मुद्दा डॉ. नरेन्द्र जाधव की रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से खुलेगा।

मातृभाषा में शिक्षा का पूर्व-निर्धारित सोच के चलते विरोध

यह दिशा निर्देश सीबीएसई द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण दिए जाने के बारे में था, आइए पहले यह देखते हैं कि यह दिशा निर्देश असल में क्या कह रहा है? यह कहता है कि बच्चे को साक्षर बनाने की पहली भाषा (जिसे आर1 से दर्शाया गया है) वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ना-लिखना सीख सके- बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगर कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं (एक से अधिक भाषाओं) के बच्चे हैं और इस वजह से यह अव्यवहारिक महसूस हो रहा है, तो बच्चों की दूसरी सबसे परिचित भाषा जो कि आम तौर पर स्थानीय रूप से प्रचलित भाषा भी होती है, को उपयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहें तो बच्चों को उस भाषा में पहले पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए जिसे वे पहले से ही जानते हैं।

नजरिया

अनुराग बेहार

लेखक अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ एवं अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर हैं। अंग्रेजी अखबार मिंट में प्रकाशित आलेख से अनुदित

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 22 मई 2025 को एक दिशानिर्देश जारी किया। कुछ अखबारों ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए संपादकीय प्रकाशित किए। ये संपादकीय और संबंधित राय के अंश बेहद भ्रामक थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इन आम तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों में जगह मिली।

यह दिशा निर्देश सीबीएसई द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण दिए जाने के बारे में था, आइए पहले यह देखते हैं कि यह दिशा निर्देश असल में क्या कह रहा है? यह कहता है कि बच्चे को साक्षर बनाने की पहली भाषा (जिसे आर1 से दर्शाया गया है) वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ना-लिखना सीख सके- बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगर कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं (एक से अधिक भाषाओं) के बच्चे हैं और इस वजह से यह अव्यवहारिक महसूस हो रहा है, तो बच्चों की दूसरी सबसे परिचित भाषा जो कि आम तौर पर स्थानीय रूप से प्रचलित भाषा भी होती है, को उपयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहें तो बच्चों को उस भाषा में पहले पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए जिसे वे पहले से ही जानते हैं।

सीबीएसई ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि आर1 को ही स्वाभाविक तौर पर दूसरे विषयों के लिए पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, जिसमें आर2 में साक्षरता भी आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है जब एक बच्चा आर1 और आर2 दोनों में साक्षरता हासिल कर लेता है तो दोनों में से किसी भी भाषा को अन्य विषय सिखाने का माध्यम बनाया जा सकता है।

यहाँ तक कि इन जगहों से आने वाली गुमराह करने वाली आलोचना भी इस बात को मानती है कि वैश्विक शोध, अनुभव और सामान्य ज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं- बच्चे उस भाषा में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ना और लिखना सीखते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मौजूदा भाषाई और सामाजिक ज्ञान भाषा सीखने में सहायक होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से ज्ञात शब्दों को लिखित प्रतीकों से जोड़ने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, अपरिचित भाषा में पढ़ना-लिखना सिखाना कठिनाई को और बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों को एक नई भाषा को भी सीखना होता है और उसमें पढ़ने और लिखने की क्षमता भी विकसित करनी होती है।

इस मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकारते हुए भी यह लिखने वाले लेखक किस तरह से गलत हैं? इस दावे में त्रुटि इस तरह से है कि- इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में 28 मई को लिखा- इस तर्क को पूरे देश के वृहद बहुभाषिक सीबीएसई पारिस्थितिक तंत्र में एक समान लागू करने में बहुत सी जटिलताएँ सामने आती हैं। ऐसे शहर और कस्बे जहां कक्षाओं में विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बच्चे आते हैं.....वहाँ विविध भाषाओं वाली कक्षा में काम करना कैसे संभव होगा ? तब किस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी?

इस तरह के बयानों से यह साबित होता है कि आलोचकों ने या तो सीबीएसई के दिशानिर्देशों को ठीक से पढ़ा नहीं या फिर समझने में विफल रहे हैं- या फिर यह भी हो सकता है कि यह इंग्लिश के

विस्थापित होने के डर से उपजा सामान्य विद्रोह है, जो कि इससे जुड़े ज़्यादातर बयानों से जाहिर होता है

सीबीएसई के दिशानिर्देशों ने पहले ही बहुभाषिक माहौल की जटिलताओं को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए बात रखी है। अगर इस तर्क के साथ जाएँ तो स्थानीय रूप से उपयुक्त भाषा को आर1 के रूप में चुनना चाहिए- जो कि बहुभाषिक जटिलता का समाधान प्रस्तुत करता है न कि दिक्कत बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के दावों में आलोचकों के द्वारा जो तर्क दिये जा रहे हैं वह दुराग्रही महसूस होते हैं क्योंकि- वे बहुभाषिक माहौल में अँग्रेजी को एकसमान रूप से लागू किए जाने की वकालत करते हैं- जो कि अप्रोच के तौर पर गहरे रूप में दोषपूर्ण और निष्क्रिय है, क्योंकि भारत के किसी भी बहुभाषिक माहौल में अधिकांश बच्चों के लिए अँग्रेजी सबसे अपरिचित भाषाओं में से एक है। इस अखबार के पढ़ने वालों के लिए एक चेतावनी है- अपने बच्चों या नाती-पोतों की छवि को देखकर मंत्रमुग्ध मत होइए- जो कि इस देश का मात्र 2 प्रतिशत भर होंगे, बाकी के 98 प्रतिशत के लिए तो अँग्रेजी अभी भी एलियन है खास तौर से उनकी शुरुआती बाल्यावस्था में ।

इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं- मान लीजिए मैंगलोर की कक्षा 1 का दृश्य है, यहाँ बच्चों की मातृभाषाओं में कन्नड़, मलयालम, उर्दू, तुलु और कोंकणी शामिल हो सकती हैं। चूँकि यह बच्चे मैंगलोर में रहते हैं इसलिए उनकी मातृभाषा के अलावा उनका परिचय कन्नड़ से है, वे अँग्रेजी जानते होंगे इसकी संभावना कम है। इसलिए आर1 के तौर पर कन्नड़ ही ठीक रहेगी, हो सकता है कि उनमें से कुछ की यह मातृभाषा हो और कुछ इससे परिचित भर होंगे। पर इसके विपरीत अँग्रेजी सबके लिए एक अपरिचित भाषा ही होगी। यह परिदृश्य पूरे भारत में देखा जा सकता है। बड़े मेट्रो शहरों में भी जिसमें प्रवासी लोग बाहर से आते हैं, वहाँ भी बच्चों की स्थानीय भाषा को जानने की संभावना अँग्रेजी जानने से अधिक है। इसलिए सीबीएसई का दिशानिर्देश देश की बहुभाषिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक तौर पर साक्षरता के लिए सही दृष्टिकोण है।

सीबीएसई के इस कदम ने व्यवस्था में सबसे गहरे तौर पर जमे मुद्दे को लक्षित किया है- साक्षरता को किस तरह से प्राप्त किया जाए, जो सभी तरह से सीखने और उसके बाद की शिक्षा का भी आधार है। हालांकि केवल एक परिचित भाषा का उपयोग अपने आप में साक्षरता की समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं है लेकिन यह केंद्रीय और आवश्यक है। शिक्षा में सुधार करने के लिए और इसे ज़्यादा न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए हमें भारत में साक्षरता दर के संकट और इसे संबोधित करने की तात्कालिकता को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

यह सोच त्वरित व अपर्याप्त है साथ ही तकनीकी शैक्षिक मुद्दों पर नियंत्रण की कमी दिखाती है कि हमारे अभिजात्य वर्ग की सोच पर अँग्रेजी कितनी मजबूती से हावी है और यह इन अखबारों के संपादकीय में साफ झलकता है। क्या कोई भी अखबार अस्पताल में हृदय रोग संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में इस तरह के भ्रामक विचार छापने की हिम्मत करेगा? नहीं, क्योंकि यह बेहद तकनीकी मामला है। फिर भी शिक्षा में सबसे तकनीकी मामलों पर भी बिना सोचे समझे इस तरह के विचार दिए जाते हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि अँग्रेजी सामाजिक और आर्थिक रूप से आकांक्षापूर्ण बनी हुई है। इसलिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि हर भारतीय बच्चा अंग्रेजी सीखे। आलोचक यह पहचानने में विफल रहे कि सीबीएसई का यह दृष्टिकोण अंग्रेजी पढ़ाने और साक्षरता दोनों के लिए कहीं अधिक प्रभावी होगा।

किसी परिचित भाषा में साक्षरता प्राप्त करना यानी पढ़ना-लिखना सीखना कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, अँग्रेजी बाद में भी सीखी जा सकती है। यह जबरदस्ती अँग्रेजी जैसी अपरिचित भाषा में साक्षरता सीखने से कहीं अलग है, जो अँग्रेजी और पढ़ना-लिखना सीखना दोनों को दुष्कर बना देता है। जिस तरीके की वकालत आलोचकों द्वारा की जा रही है वह न केवल साक्षरता बल्कि अँग्रेजी सीखने को भी और मुश्किल कार्य बना देगा। भारत के हजारों तथाकथित अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में से किसी में भी जाएँ, और आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ने-लिखने और अंग्रेजी सीखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें सीबीएसई के शैक्षणिक रूप से सही और साहसी दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए, न कि इसकी निंदा करनी चाहिए।

राजनीति

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

आम आदमी और मुद्दों से कोसों दूर कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी के द्वारा मप्र में अपने संगठन को मजबूत करने और नये सिरे से पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक,संगठनतात्मक बदलाव को लेकर पर्यवेक्षको के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया करवाई जा रही है। और कहां जा रहां है कि इससे कांग्रेस संगठन मजबूत होगा,प्रयास और सोच अच्छी है,लेकिन हकीकत में कांग्रेस पार्टी आम आदमी और जमीनी मुददो से कोसों दूर है।

सन् 2018 में 15 सालो के बाद मप्र की सत्ता में वापस आई कांग्रेस पार्टी आपसी खीचतान के चलते,पंद्रह महीने बमुश्किल अपनी सरकार चला पाई,आपसी अंर्तकलह के चलते सत्ता से बाहर तो हो ही गई कई कांग्रेसी पार्टी छोड़कर चले गये तो कई पार्टी विधायको ने विपक्ष को सहयोग देकर उन्हे सत्तारूढ कर दिया,इन 15 महीनों के शासन में कांगेस पार्टी न तो संगठन मजबूत कर पाई नही कार्यकर्ताओं को एक कर सकी आपसी आरोप प्रत्यारोप के चलते 2023 में मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ऐसा जताया कि वही सरकार बना रही है, लेकिन हुआ वह सबके सामने है। और इस चुनाव में जो बचे हुये असंतुष्ट कांग्रेसी थे,उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो कई कांग्रेसजन दबाव के चलते चुनाव से दूर हो गए।

वर्तमान समय मे मप्र में पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक गिनती के नेता और जनप्रतिनिधी बचे है जो आम आदमी,समाज,गांव,नगर की विभिन्न समस्याओ के लिये आगे आते होंगे,न ही आमजनो से मिलने के लिये पदाधिकरी उपस्थित रहते,प्रदेश के कई जिलो में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय चुनाव के अवसरो को छोडकर सुने नजर आते है।

कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेता भी नहीं है जो सरकार की योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने पर मुखर होकर मोर्चा खोल सके,साथ ही साथ पंचायत से लेकर जिले तक इनका परीक्षण कर सके योजना क्या है और इसका लाभ वास्तविक हितग्राहियों को मिल पा रहा है या नहीं। और ये योजनाए कोई नई नहीं है आम समस्या बिजली, पानी, सड़क शिक्षा और स्वास्थ राशन रोजगार से जुडी हुई है साथ ही आम आदमी के काम पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय से ज्यादा के नही होते है, लेकिन उन कार्यो में उसकी मदद के लिये नियमित सहयोग करने वाले नहीं है।

केन्द्र व राज्य सरकार कई ऐसी योजनाए है, जिसमें भ्रष्टाचार की बाते तो कांगेसजन करता है लेकिन उसे पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाता है,नहीं उसकी तह में पहुच पाता है,आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करना था लेकिन यह आज भी कई गांवों में पूर्ण नही हो पाई है कई ग्रामों के निवासी आज भी पानी की समस्या से जुझ रहे है लेकिन कांगेसजन उस पर कुछ करना ही नहीं चाहते है। बीते गर्मी के मौसम में भाजपा व कांगेस के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुये पानी के टेंकरों का वितरण सम्बन्धित पंचायतों को किया है,जो बताता है कि हर घर पानी नहीं पंहुचा।

केन्द्र सराकर की एक और महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है,जिसे गांव,गांव जाकर देखने के साथ यह भी पता करना चाहिये जिन्हे सालों बाद भी लाभ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उदाहरण के लिये बड़वानी जिले की जनपद बड़वानी के ग्राम आमलियापानी के जुरदार सिंह को आज तक आवास नहीं मिला,वे बताते है पंचायत सचिव कहता है तुम्हे नहीं मिलेगा क्यों कि तुम इसका लाभ ले चुके हो,जुरदार का कहना है तो मेरी कुटीर कहां बनी है पंचायत बताये। ऐसी और कितनी समस्या हो सकती है।

आज बेहतर रोजगार के लिये आदिवासी जिलों से प्रतिदिन सैकड़ोजन अन्य प्रदेशों में रोजगार हेतु पलायन करते है उसके बारे में गम्भीरता से कोई विचार नही करता है गाहे बगाहे किसी नेता का बयान आ जाता है लेकिन कोई यह नही पूछता है कि हमारे प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं है।

दूसरी और प्रदेश सरकार स्वास्थ और शिक्षा निजीकरण कि और बढ़ रही है बड़वानी जिला चिकित्सालय के एक प्रयोगशाला कर्मचारी ने बताया कि लेबोटरी से लगाकर सोनोग्राफी तक निजी हाथों में जा रही है सरकार तकनीकी कर्मचारियों कर भरती नहीं कर रही है आने वाले समय में सब कुछ निजी रहेगा,ऐसा ही कुछ शिक्षा के क्षैत्र में चल रहां है और उसकी शुरुआत तीन साल पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक सिहोर जिला मुख्यालय में स्थित शा.कन्या शिक्षा परिसर से हो चुकी है।

जन सामान्य से जुड़े ऐसे मुददे है जिसपर कांग्रेस के नेता मौन साधे है जबकि इनपर स्थानीय स्तर से प्रदेश स्तर तक मुखरता आवश्यक है नहीं तो आने वाले समय में निजीकरण को कोई नहीं रोक पायेगा।

बांग्लादेश में कट्टरवाद

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

लोकतंत्र और सांस्कृतिक अस्मिता पर संकट

बांग्लादेश आज जिस राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रहा है, वह केवल आंतरिक सत्ता-संघर्ष या चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है। यह संकट कहीं गहरा, बहुआयामी और चिंताजनक है। एक ओर जहां बांग्लादेश की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और प्रशासनिक स्थिरता की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस्लामी कट्टरवाद की लहर फिर से सिर उठा रही है। यह लहर केवल धार्मिक उन्माद नहीं, बल्कि एक संगठित वैचारिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान, अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को खत्म करना है।

राजनीतिक वैक्यूम में कट्टरपंथी ताकतों का उदय- मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार की कमजोर नीतियों और प्रशासनिक असफलताओं ने कट्टरपंथी संगठनों को खुलकर सांस लेने का मौका दे दिया है। हिफाजत-ए-इस्लाम, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (आईएबी), खिलाफत मजलिस (चरू), बांग्लादेश खिलाफत मजलिस (बीकेएम), जमीयत उलमा-ए-इस्लाम और नेजाम-ए-इस्लाम (एनआई) जैसे संगठन अब सड़कों पर आक्रामक रैलियों और सांप्रदायिक नारों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं।

3 मई, 2025 को ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम की विशाल रैली इसका ताजा उदाहरण है। फरवरी 2026 में संभावित आम चुनावों के मद्देनज़र इन इस्लामी दलों ने एक संपर्क समिति भी बना ली है। उनकी रणनीति स्पष्ट है–धार्मिक भावनाओं को भड़का कर और सामाजिक ध्रुवीकरण कर वोट बैंक तैयार करना।

चुनावी समीकरणों में कट्टरवाद का समीकरण- इतिहास गवाह है कि इन दलों की चुनावी उपलब्धियां सीमित रही हैं। 1991 से लेकर 2008 तक के चुनावी आँकड़े बताते हैं कि जमात-ए-इस्लामी समेत अधिकांश इस्लामी दलों की सीटें नगण्य रहीं। फिर भी यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब भी इन दलों ने गठबंधन की राजनीति की, उन्होंने सत्तासीन होकर लोकतंत्र विरोधी और असहिष्णु नीतियों को बढ़ावा दिया। 2001 से 2006 तक बीएनपी-जमात गठबंधन सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, पत्रकारों का उत्पीड़न और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर हमले इसके ज्वलंत उदाहरण रहे हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर सुनियोजित हमला- कट्टरपंथी संगठनों का असली एजेंडा केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। वे बांग्लादेश के सामाजिक ताने-बाने, सांस्कृतिक गतिविधियों और महिलाओं की स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। संगीत, थिएटर, महिला फुटबॉल मैच, पतंग उत्सव जैसे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 'इस्लाम विरोधी' बताकर रोका जा रहा है।

महिला सुधार आयोग की सिफारिशों पर जिस तरह से इन संगठनों ने उग्र विरोध और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, वह उनकी स्त्री विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। विवाह के भीतर बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने, यौनकर्मियों के श्रम अधिकार सुनिश्चित करने जैसे सुधारात्मक प्रस्तावों पर उनका आक्रोश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी नफरत का परिचायक है।

अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और प्रशासनिक मूकदर्शिता- हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिरों, घरों और व्यवसायों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन अंतरिम सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। जो घटनाएँ हो रही हैं, उनमें प्रशासन की भूमिका अधिकतर 'मूकदर्शक' जैसी रही है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए गंभीर सामाजिक विघटन का कारण बन सकती है।

अंतरिम सरकार का ढुलमुल रवैया- सरकार की असफलता केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्पष्टता के अभाव में भी दिख रही है। जब धार्मिक मामलों का सलाहकार स्वयं हिफाजत-ए-इस्लाम और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश का सक्रिय सदस्य हो, तब सरकार से कट्टरपंथियों पर कठोर कार्रवाई की उम्मीद करना निरर्थक है। सरकारी मंचों से 'इस्लामी संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने' की घोषणाएँ इस चिंता को और प्रगाढ़ कर देती हैं कि क्या प्रशासन जानबूझकर इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है?

बांग्लादेश का भविष्य: संघर्ष या आत्मसमर्पण?- आज बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। या तो देश का नागरिक समाज, मीडिया, प्रबुद्ध वर्ग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इस कट्टरपंथी खतरे का सामना करेंगे, या फिर बांग्लादेश एक बार फिर लोकतंत्र, मानवाधिकार और सांस्कृतिक विविधता से पीछे हटकर धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की दलदल में फंस जाएगा।

जरूरत इस बात की है कि अंतरिम सरकार कठोर इच्छाशक्ति दिखाए, सांप्रदायिक तत्वों पर शिकंजा कसे और अल्पसंख्यकों व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए यह संघर्ष आज निर्णायक बन चुका है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

संजय तैलंग

लेखक व्यंग्यकार हैं।

फूलों की चोरी से फूले न समाते फूल चोर

सुबह की सैर अच्छी सेहत के लिए प्राणवायु है। और हो भी क्यों नहीं, सुबह खुशनुमा मौसम और ताजा हवा का साथ मिलने से शरीर दिनभर तरोताजा जो बना रहता है। सारे दिन ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहती है। हर काम में मन लगता है, काम में गति से संपन्न होते हैं। भोजन को पचाने में अमाशय को अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ती। गोडे (घुटने) भी बराबर काम करते हैं। सुबह की सैर के इन फायदों में अब एक फायदा और जुड़ गया है। इसका नाम है पूजा के लिए फूलों की जुगाड़। चूंकि, यह मामला सीधे जेब से जुड़ा है, इसलिए इसे विशेष फायदों में गिना जा सकता है।

सुबह की सैर पर नियमित जाने वालों ने उनकी तरह ताजा हवा खाने निकले अनेक लोगों के हाथों में प्लास्टिक (पोलीथिन) की थैली देखी होगी। सुबह-सुबह सेहत के लिए हार्मफुल इस उत्पाद को देख हैरत में पड़ जाने वाले 'सुबह के सैलानी' शायद इस थैली की महिमा नहीं जानते। वैसे वे जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि सेहत के लिए सही न मानी जाने वाली एक अदद थैली के बारे में विचार कर वे सुबह की सैर का मजा किरकिरा करना नहीं चाहते। बहरहाल, वे अपनी ही धुन में रमे कदम बढ़ाए जा-खुशियों के गीत जाए जा के साथ अपने काम (सैर) पर ही फोकस रखते हैं।

दरअसल, हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए सुबह की सैर पर निकले ये कतिपय 'सुबह के ये सैरिये' 'एक पंथ दो काज' के मुहावरे को पूरी तरह सार्थक कर रहे हैं। 'सुबह की सैर की सैर' और 'घर में विराजित देवों के लिए फूलों की जुगाड़' अलग से और वह भी बिल्कुल मुफ्त। बाजार से फूल लाने पर पांच-दस रुपए गांठ से ढीले करने पड़ते, लेकिन सुबह-सुबह फूलों से भरे उनके प्लास्टिक बैग के लिए उन्हें एक ढेला नहीं देना। और तो और दोहरे लाभ से फूले न समाते उन सुबह के सैरियों की आवाज में अलग खनक भी सुनी जा सकती है 'आज तो थैली पूरी भर गई। कम से कम बीस रुपयों के तो होंगे। आज यही बीस रुपए कमाए।'

जाहिर है जिन्होंने घर के ग्रीन बेल्ट में फूलों के पौधे लगाकर उन्हें जतन से सींचा, खाद-पानी देकर बड़ा किया, उन्हें देर से जागने की कीमत अपने गंजे हो चुके पौधों के रूप में चुकानी ही है। फूल चोरों को कोस कर सुबह-सुबह अपना मूड बिगाड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि, गमलों-क्यारियों में लगे सुंदर फूलों को न देख मन मसोसना या उसके लिए जिम्मेदारों को कोसने से डाल से टूटे फूल तो वापस आने से रहे!

मन को हल्का करने के लिए वे पौधों की सूनी डालों को देख बुझे मन और लाल आंखों से चार सिक्के सुनाकर मन को हल्का करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उनके मुखारविंद से निकले सिक्के हवा में तैर कर शुद्ध हवा को थोड़ा प्रदूषित कर, थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं।

अब बात उन लोगों की, जो घरों में विराजित भगवान की पूजा के लिए सुबह-सुबह फूलों की चोरी जैसा अपराध कर आए हैं। चंद रुपए बचाने के लिए किसी का मन दुखाने का उन्हें जरा भी मलाल नहीं, प्रभु पर चोरी के फूल चढ़ाने का भी उन्हें कोई भय नहीं। ऊपर से कुछ रुपए बचाने की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलकती देखी जा सकती है। दरअसल, डालियों से फूलों को अलग करने की उनकी सोच कुछ अलग है, 'पौधे और फूल तो प्रकृति की इंसानों को देन हैं, यदि उन्हें अपनी थैली में रख लिया, तो क्या बुरा किया।' इस पॉजिटिव सोच के साथ अगले दिन दूने उत्साह से फूलों की चोरी का प्लान भी उनके दिमाग में कुलांचे भरने लगता है।

उधर, चोरी के फूलों से सजे अंतर्यामी प्रभु नादान भक्त की सोच पर हैरान हैं। सोच रहे होते हैं, कैसा भक्त है! मेरी सब कुछ जानने की शक्ति से वाकिफ होने का भी इसे डर नहीं। चोरी के फूलों से मेरी अर्चना करने की इसे क्या सजा दी सकती है! इसी पसोपेश में प्रभु आगे सोचना बंद कर, बस कृपा बरसाने वाला हाथ पीछे खींच फिर प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं।

दृष्टिकोण

भारत डोगरा

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

लोगों को जोड़ने के लिए अहिंसक आंदोलन

इस स्थिति में यदि भारत में कोई ऐसा अहिंसक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन उभरता है जिसकी सोच देश के साथ पूरे विश्व की भलाई की सोच हो, जो इसके लिए निरंतरता से व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ सकता है व जो बुनियादी बदलाव की राह पर चलते हुए साथ में बहुत से लोगों के दुख-दर्द को कम करते हुए आगे बढ़ता है तो यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसका लाभ देश के साथ विश्व स्तर पर भी मिल सकेगा। इसके पहले कदम के रूप में जरूरी है कि दुनिया और देश के स्तर पर जो आगे की उचित राह होनी चाहिए उसके बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जाए। इतना तो मानकर चला जा सकता है कि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं - न्याय व समता, अमन-शांति व अहिंसा, पर्यावरण व जैव-विविधता की रक्षा, लोकतंत्र व पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण व बढ़ता आपसी सहयोग तथा बेहतर सामाजिक संबंध।

महात्मा गांधी की विरासत स्वतंत्र भारत में अनेक अहिंसक आंदोलनों के रूप में फलती-फूलती रही है। इससे कई सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद इस समय देश में निरंतरता से सार्थक बदलाव को आगे बढ़ाने वाले किसी बड़े व व्यापक प्रयास का अभाव है। वास्तव में पूरे विश्व स्तर पर ही बढ़ते अनिश्चय व गंभीर होती समस्याओं के बीच वैचारिक संकट है व परिपक्व माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी मनमानी के निर्णय लिए जा रहे हैं।

इस स्थिति में यदि भारत में कोई ऐसा अहिंसक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन उभरता है जिसकी सोच देश के साथ पूरे विश्व की भलाई की सोच हो, जो इसके लिए निरंतरता से व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ सकता है व जो बुनियादी बदलाव की राह पर चलते हुए साथ में बहुत से लोगों के दुख-दर्द को कम करते हुए आगे बढ़ता है तो यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसका लाभ देश के साथ विश्व स्तर पर भी मिल सकेगा।

इसके पहले कदम के रूप में जरूरी है कि दुनिया और देश के स्तर पर जो आगे की उचित राह होनी चाहिए उसके बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जाए। इतना तो मानकर चला जा सकता है कि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं - न्याय व समता, अमन-शांति व अहिंसा, पर्यावरण व जैव-विविधता की रक्षा, लोकतंत्र व पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण व बढ़ता आपसी सहयोग तथा बेहतर सामाजिक संबंध।

इन सिद्धांतों के आधार पर देश और दुनिया की भावी राह तय करने के साथ इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना जरूरी है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन सिद्धांतों का कैसे उपयोग किया जाए? अपना, आसपास का जीवन, देश व दुनिया की स्थिति बेहतर करने के लिए इन सिद्धांतों के आधार पर क्या राह निकाली जाए? यह सवाल बहुत जरूरी है व सही शिक्षा की प्राप्ति और प्रसार तो ऐसे सवालों के उत्तर खोजने में ही निहित है।

एक ओर ऐसे आंदोलन को इन सिद्धांतों के आधार पर देश और दुनिया की आज से कहीं बेहतर व्यवस्था की पहचान बनानी होगी। यह कुछ इस तरह किया जाएगा कि एक ओर लोगों का दुख-दर्द बहुत कम किया जा सके तथा दूसरी ओर धरती की जो जीवन क्षमताएं संकटग्रस्त हो गई हैं, उन्हें समय रहते बचा लिया जाए तथा इस तरह भावी पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित किया जाए। इस विमर्श व नियोजन में जरूरी है कि जो समाधान सामने आएं वे एक-दूसरे से मेल रखने वाले हों तथा सभी मनुष्यों के साथ अन्य जीवन-रूपों की भलाई पर भी समुचित ध्यान दिया जाए।

दूसरी ओर, इस आंदोलन को चाहिए कि वह ऐसी राह अपनाए जिस पर चलते हुए बहुत से लोग अपने दुख-दर्द को कम कर सकें। अन्याय व विषमता कम होने से तो दुख-दर्द कम होते ही हैं, साथ में तरह-तरह के नशे, दैनिक जीवन में हिंसा, टूटते बिखरते सामाजिक संबंधों जैसी समस्याओं के कम होने से भी दुख-दर्द कम होता है। अतः आंदोलन की बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ते हुए ऐसे सतत् रचनात्मक प्रयास करने चाहिए जिससे कि सभी तरह के दुख-दर्द कम होते जाएं व इस आधार पर अनेक लोग आंदोलन से जुड़ते रहें।

अन्याय व विषमता के विरुद्ध संघर्ष करने के साथ-साथ ऐसे बहुत से रचनात्मक कार्य जरूरी हैं जिनसे टिकाऊ रोजगार बढ़ते हैं, किसानों व दस्तकारों की आजीविका मजबूत होती है, गांवों की आत्म-निर्भरता बढ़ती है और आपसी सहयोग से समस्याएं कम होती हैं। इस तरह के रचनात्मक प्रयासों को निरंतरता से बढ़ाना चाहिए। समता व पर्यावरण रक्षा आधारित सामुदायिक जीवन के अनेक प्रयोग करने चाहिए जो वैकल्पिक जीवन की राह प्रस्तुत करें।

ऐसे आंदोलन का एक चुनावी राजनीतिक पक्ष भी होना चाहिए। इसके अन्तर्गत पहले स्थानीय और फिर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में राजनीतिक दल बनाकर उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं या स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन दिया जा सकता है। आंदोलन अपनी राह पर चलता रहेगा व चुनावी राजनीति के लिए कोई समझौते नहीं किए जाएंगे। अपनी राह पर चलते हुए जितनी चुनावी सफलता मिले या न मिले, उसे स्वीकार करते हुए आंदोलन अपनी राह पर बना रहेगा।

इस आंदोलन को अहिंसक होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक तौर-तरीके व पारदर्शिता अपनाना चाहिए। उसकी सभी गतिविधियां गुप्त न होकर सार्वजनिक व पारदर्शी हों। धन प्राप्त करने के स्रोत, हिसाब-किताब सभी पारदर्शी होने चाहिए। यदि कोई सदस्य आंदोलन से एक होते हुए कुछ मुद्दों पर अलग राय रखता है, तो उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ऐसे आंदोलन की अपनी राह और अपने विकल्पों को आगे ले जाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए व दूसरों की या विरोधियों की कटु आलोचना पर अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। जहां आलोचना जरूरी हो वहां वह मर्यादित व शालीन रहे।

आंदोलन को चाहिए कि स्वयं पूरी तरह अहिंसक होते हुए अपने संघर्षशील साथियों की रक्षा के पूर्ण प्रयास करें तथा जहां किसी का उत्पीड़न हो, उस साथी को समुचित सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करें। वैसे भी आंदोलन के सभी सदस्यों में परस्पर सहायता व सहयोग की स्थिति बढ़ती रहना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर गांवों व बस्तियों में, शहरों व महानगरों में आंदोलन को अपने सदस्यों व समर्थकों को ऐसी जगह देनी चाहिए जहां वे गीत-संगीत के बीच प्रेरणादायक स्थितियों में अपने विभिन्न साथियों के साथ बेहतर जीवन व बेहतर दुनिया के नियोजन व सपनों को जी सकें व प्रेरणादायक स्थितियों में अपना योगदान दे सकें। (सप्रेस)

स्कूल का प्रथम दिन

श्याम कुमार कोलारे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

नई दुनिया की ओर बच्चों का पहला कदम

स्कूल खुलने के समय सबसे अधिक उत्साह उन छोटे बच्चों में होता है जो पहली बार स्कूल का अनुभव लेने जा रहे होते हैं। ये बच्चे घर के लाड़-प्यार और दुलार से निकलकर एक ऐसे नए संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें शिक्षा की पहली दीक्षा मिलती है। माता-पिता की गोद छोड़कर शिक्षक की उँगलियों को पकड़कर चलने की शुरुआत उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का पहला चरण होती है। इन बच्चों के लिए स्कूल एक नई दुनिया होती है - नई जगह, नए लोग, नए दोस्त, नए नियम और नई दिनचर्या। यह परिवर्तन उन्हें उत्साहित तो करता ही है, साथ ही थोड़ी घबराहट और डर भी उनके मन में होता है। परंतु धीरे-धीरे जैसे ही वे कक्षा और शिक्षक से परिचित होते हैं, स्कूल उनका दूसरा घर बन जाता है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात जैसे ही स्कूल पुनः खुलते हैं, एक नई उमंग, उत्साह और उल्लास का वातावरण निर्मित होता है। विशेष रूप से यह दृश्य जून के मध्य में अधिक देखने को मिलता है, जब गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालयों में बच्चों की चहचहाहट और किलकारियाँ एक बार फिर लौट आती हैं। दो महीने तक शांत पड़ी स्कूल की इमारतें, प्रांगण, कक्षा-कक्ष और पुस्तकालय अब बच्चों की भाग-दौड़, शोरगुल और हँसी-मजाक से फिर जीवंत हो उठते हैं। यह दृश्य न केवल शिक्षकों के लिए सुखद होता है बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश लाता है - शिक्षा का क्रम पुनः आरंभ हो चुका है। स्कूल खुलने के समय सबसे अधिक उत्साह उन छोटे बच्चों में होता है जो पहली बार स्कूल का अनुभव लेने जा रहे होते हैं। ये बच्चे घर के लाड़-प्यार और दुलार से निकलकर एक ऐसे नए संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें शिक्षा की पहली दीक्षा मिलती है। माता-पिता की गोद छोड़कर शिक्षक की उँगलियों को पकड़कर चलने की शुरुआत उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का पहला चरण होती है। इन बच्चों के लिए स्कूल एक नई दुनिया होती है - नई जगह, नए लोग, नए दोस्त, नए नियम और नई दिनचर्या। यह परिवर्तन उन्हें उत्साहित तो करता ही है, साथ ही थोड़ी घबराहट और डर भी उनके मन में होता है। परंतु धीरे-धीरे जैसे ही वे कक्षा और शिक्षक से परिचित होते हैं, स्कूल उनका दूसरा घर बन जाता है।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा केवल अक्षरों और संख्याओं को जानने तक सीमित नहीं है। यह वह समय होता है जब बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। स्कूल में उन्हें व्यवहार, अनुशासन, सामाजिकता, सहभागिता, सहयोग, भावनाओं की अभिव्यक्ति और समस्याओं को सुलझाने जैसे गुणों की भी शिक्षा मिलती है। शिक्षक उन्हें न केवल किताबों का ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। एक बच्चा जब विद्यालय आता है तो वह केवल एक छात्र नहीं होता, बल्कि एक भविष्य का नागरिक होता है। प्रारंभिक शिक्षा उसकी सोच, आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की नींव होती है। यदि इस स्तर पर उसे उपयुक्त वातावरण, प्रेरणा और मार्गदर्शन मिले, तो उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। शिक्षक बच्चों के लिए पहले सामाजिक संरक्षक होते हैं। विशेषकर स्कूल के शुरुआती दिनों में बच्चों को अपने परिवार से दूर होकर अनजानी दुनिया में ढलने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका केवल एक पढ़ाने वाले तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें एक मार्गदर्शक, मित्र, अभिभावक और सहायक की भूमिका भी निभानी होती है।

एक संवेदनशील शिक्षक बच्चे की शंकाओं को दूर कर उसे सहज बनाने का प्रयास करता है। वह उनके मन में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है, डर को खत्म करता है और सीखने को एक आनंदमय अनुभव बनाता है। शिक्षक अपने अनुभवों से बच्चों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान देता है, बल्कि उन्हें सामाजिकता, सहयोग और सहिष्णुता भी सिखाता है। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं रह सकती। जब बच्चा घर से स्कूल आता है, तो उसे शिक्षा की यात्रा में निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है। अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो केवल शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी प्रदान करते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, उनकी रुचियों को समझें, उन्हें खुलकर सवाल पूछने दें और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, संस्कारों की नींव भी घर से ही डलती है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों में अनुशासन, आदर, प्रेम, करुणा और कर्तव्यबोध जैसे गुणों का भी बीजारोपण करना चाहिए विद्यालय केवल शिक्षकों और विद्यार्थियों की संस्था नहीं होती, वह समाज का भी एक अभिन्न अंग है। एक जागरूक समाज ही एक समर्थ और समर्पित शिक्षा व्यवस्था को जन्म दे सकता है। जब समुदाय स्कूल से जुड़ता है - चाहे वह स्थानीय स्वराज संस्थाएं हों, युवा स्वयंसेवक हों या वरिष्ठ नागरिक - तो बच्चों को जीवन से जुड़े अनुभव, प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता है। आज देशभर में कई स्थानों पर विद्यालय समुदाय के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय भाषा, संस्कृति, पारंपरिक खेल, कहानियाँ, गीत और लोकज्ञान को विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित करने से बच्चों को जड़ों से जोड़ना संभव होता है।

आज के बदलते समय में यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा प्रणाली बालकेंद्रित हो। प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है - उसकी रुचि, समझने का तरीका, सीखने की गति और भावनात्मक आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। ऐसे में शिक्षक और विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार लचीली और संवेदनशील शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। स्कूल का पहला दिन केवल एक तिथि नहीं होती, वह एक नए जीवन अध्याय की शुरुआत होती है। बच्चों की किलकारियों से गूंजते विद्यालय केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं होते, वे भविष्य की प्रयोगशालाएं होते हैं जहाँ अगली पीढ़ी तैयार होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करें जहाँ हर बच्चा न केवल ज्ञान प्राप्त करे, बल्कि आनंदित होकर सीखे, अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाने और समाज के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। स्कूल खुलने के इस मौसम में जब हर बच्चा अपनी नन्हीं आँखों में सपनों की चमक लिए कक्षा में प्रवेश करता है, तब हमारा कर्तव्य है कि हम उसके उन सपनों की उड़ान को सही दिशा दें – क्योंकि यही बच्चे कल देश का भविष्य गढ़ेंगे।

गौतम घोष की फ़िल्म: परिक्रमा

सुनील शुक्ल

(लेखक भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे से प्रशिक्षित स्वतंत्र वृत्तचित्र फ़िल्मकार हैं)

विकास के विरुद्ध विकास : नर्मदा की सच्ची परिक्रमा

फ़िल्म की कहानी मुख्यतः विकास, विस्थापन और पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले एक ईमानदार इतालवी लेखक-निर्देशक अलेक्ज़ेंड्रो उर्फ़ एलेक्स (मार्को लियोनार्डी) के माध्यम से खुलती होती है, जो अमृतलाल वेगड़ की नर्मदा पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक पढ़कर इस नदी के सौंदर्य और आत्मिक चेतना से गहरे प्रभावित होता है। वह नर्मदा की परिक्रमा और उससे जुड़ी आस्था पर एक फ़िल्म बनाना चाहता है। भारत रवाना होने से पहले वह अपने किशोर पुत्र को उसकी दादी के साथ रहने के लिए तैयार करता है – एक ऐसा पुत्र को जो माँ के बिना बड़ा हो रहा है।

आज से क़रीब तीस बरस पहले 1990 में, मंडला ज़िले की डिंडोरी तहसील (जो अब ज़िला बन चुका है) में बैगा जनजाति के फ़िल्मांकन के दौरान एक अद्भुत दृश्य ने ध्यान खींचा। तीन-चार से लेकर आठ-दस लोगों के जत्थे – जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे – ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्रों में, 'नर्मदे हर' का उद्घोष करते हुए नर्मदा किनारे शांत गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। यह दृश्य कुछ रहस्यमय सा लगा। बाद में चाय की एक गुमटी पर पता चला कि वे लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। उस समय तक हमें पुण्यसलिला नर्मदा की महिमा का संज्ञान नहीं था। हम तो गंगा-गोमती के घाटों के अभ्यासी थे, जहाँ केवल गंगा की ही महिमा-कथा प्रचलित थी। बाद में ज्ञात हुआ कि नर्मदा संभवतः विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी विधिपूर्वक परिक्रमा की जाती है, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ – जिसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है।

'परिक्रमा' गौतम घोष की नवीनतम फ़िल्म है जो 27 जून को प्रदर्शित हुई। यह एक भारत-इतालवी संयुक्त निर्माण है जिसकी परिकल्पना क़रीब दो दशक पहले की गई थी। समानांतर सिनेमा के गंभीर, प्रयोगधर्मी फ़िल्मकार गौतम घोष ने इस बार आध्यात्मिकता, पर्यावरण और विस्थापन की त्रयी को एक गहन संवेदनशीलता के साथ रूपायित किया है।

फ़िल्म की कहानी मुख्यतः विकास, विस्थापन और पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले एक ईमानदार इतालवी लेखक-निर्देशक अलेक्ज़ेंड्रो उर्फ़ एलेक्स (मार्को लियोनार्डी) के माध्यम से खुलती होती है, जो अमृतलाल वेगड़ की नर्मदा पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक पढ़कर इस नदी के सौंदर्य और आत्मिक चेतना से गहरे प्रभावित होता है। वह नर्मदा की परिक्रमा और उससे जुड़ी आस्था पर एक फ़िल्म बनाना चाहता है। भारत रवाना होने से पहले वह अपने किशोर पुत्र को उसकी दादी के साथ रहने के लिए तैयार करता है – एक ऐसे पुत्र को जो माँ के बिना बड़ा हो रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता रूपा (चित्रांगदा सिंह) की किताब से उसे नर्मदा नदी पर बन रहे बाँधों और उससे उत्पन्न डूब क्षेत्र की पर्यावरणीय और मानवीय त्रासदी का पता चलता है। रूपा फ़िल्म की सूत्रधार (एंकर) बनती है। टीम के साथ फ़िल्मांकन के दौरान एलेक्स की मुलाक़ात मंदिर के आसपास फेरीवाले किशोर 'लाला' (आर्यन बड़कुल) से होती है। होशियार लाला कई सारी भाषाएँ थोड़ी-थोड़ी बोलता है और एलेक्स को एक जादुई पत्थर दो हज़ार रुपये में बेच देता है। वो लाला से और बात करना चाहता है और जब एलेक्स उससे पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया, तो लाला एक गहरी मुस्कान के साथ कहता है – 'हमरा नसीब (मेरा दुर्भाग्य)।'

रूपा से इस वाक्य का अर्थ समझकर एलेक्स के भीतर एक नई संवेदना जन्म लेती है। एलेक्स विकास के नाम पर अबोध, सरल और सहनशील ग्रामीणों के जबरन विस्थापन से व्यथित होता है और वह इस अन्याय पर अपना आक्रोश ज़ाहिर करता है। शाम को शूटिंग के बाद चर्चा के दौरान एलेक्स रूपा और अपने कैमरामैन बिजॉय से लाला का ज़िक्र करता है और उसकी फ़ोटो दिखाता है। बिजॉय लाला की बोलती आँखों से प्रभावित होता है। एलेक्स को वहाँ एक पुरातन महक की अनुभूति होती है। पर्यावरण सजग एलेक्स अब लाला को केंद्र में रखकर विस्थापन की कहानी कहना चाहता है।

शुरू में रूपा इस नई दिशा का विरोध करती है – उसे लगता है कि एलेक्स आस्था की कथा को 'पीड़ा' में बदलकर बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में वह सहमत होती है और लाला को दस-बारह दिन के लिए फ़िल्म में भाग लेने को राज़ी कर लेती है। यहीं से शुरू होती है विस्थापन की उस अनकही त्रासदी की मार्मिक कथा, जो आज भी हमारी नदियों के किनारे ख़ामोश बह रही है।

श्रद्धाभाव से की जा रही एक नदी की परिक्रमा का फ़िल्मांकन अचानक एक सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ – डूब, विस्थापन और विखंडन – में कैसे तब्दील हो जाता है, यह अनुभव अत्यंत प्रभावशाली है। फ़िल्म 'विकास' की उस राजनीति को भी दिखाती है जिसने नर्मदा घाटी में बसे हज़ारों लोगों को उखाड़ फेंका और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचाई। रूपा का एक संवाद फ़िल्म के केंद्रीय भाव को बहुत मार्मिकता से कहता है – 'विकास ही विकास के विरुद्ध था।'

नर्मदा नदी और नर्मदा घाटी के अत्यंत सुंदर दृश्य और बाढ़-डूब के उतने ही विहंगम दृश्यों को बेहद खूबसूरती से फ़िल्माया गया है। फ़िल्म में भारतीय और इतालवी लोकसंगीत का प्रयोग, उनका संपादन और संयोजन फ़िल्म की आत्मा में रच-बस जाते हैं। साउंड डिज़ाइन एक और सशक्त पहलू है फ़िल्म का। यह सब मिलकर फ़िल्म को एक वृत्तचित्रनुमा सिनेमाई पूर्ण अनुभव बनाते हैं। फ़िल्म की शूटिंग मुख्यतः अमरकंटक, मंडला, भेड़ाघाट, बड़वानी, महेश्वर और ओंकारेश्वर में हुई है। इसके अलावा इटली में नेपल्स भी रमणीक चित्रित हुआ है।

आर्यन बड़कुल द्वारा निभाया गया 'लाला' मासूमियत और चपलता का अनोखा संगम है। एलेक्स जब अपने बेटे की तुलना लाला से करता है – 'दोनों के दर्द हैं - एक मातृत्व विहीन है, दूसरा मातृभूमि विहीन' – तो वह सिर्फ़ संवाद नहीं, एक युगबोध बन जाता है। लाला की घर लौटने की आस में उसका कहना कि – 'माँ से कहूँगा दाल-चावल के साथ अपनी वाली चटनी खिलाओ, बहुत भूख लगी है कई दिनों से' – दर्शक की आँखें नम कर देती है।

मार्को लियोनार्डो इटली के जानेमाने अभिनेता हैं। वो एलेक्स के किरदार में पूरी गहराई के साथ उतरते हैं। चित्रांगदा सिंह, अपने ग्लैमर से इतर, बेहद प्रभावशाली और सच्ची लगती हैं – विशेषतः लाला के साथ उनके संवादों में।

फ़िल्म की दृश्य भाषा जितनी प्रामाणिक और संवेदनशील है, उतनी ही कमी भाषिक स्तर पर महसूस होती है। मंडला और निमाड़ अंचल की विशिष्ट बोलियों – विशेषकर निमाड़ी के लहजे और उच्चारण – का न होना थोड़ा खटकता है। निमाड़ी बोली की अनुपस्थिति संवादों को थोड़ा सपाट बनाती है।

अंग्रेज़ी सबटाइटल्स के साथ अंग्रेज़ी, इतालवी और हिंदी मिश्रित 118 मिनट की यह फ़िल्म केवल एक सिनेमाई यात्रा नहीं, बल्कि एक गहन अंतर्यात्रा है। परंपरा, श्रद्धा, सवाल और स्मृति के बीच बहती यह कथा माँ नर्मदा के बहाने हमारे समय के सबसे कठिन और असहज प्रश्नों से साक्षात्कार कराती है – और दर्शक को भीतर तक छू जाने वाला एक नया अनुभव सौंप जाती है।

पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त कर आरोपी को

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 30 जून 2025 को चिखलार के कोटवार मनोज ने सूचना दी गई कि ग्राम चिखलार में अकेली रहने वाली महिला बबली भुसुमकर का शव संदिग्ध परिस्थिति में उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और मृतिका का मर्ग पंचनामा कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। घटनास्थल को सुरक्षित कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। प्रभारी सीन ऑफ क्राइम निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए एवं घटनास्थल की विधिवत फोटोग्राफी कराई गई। मृतिका के शव का जिला चिकित्सालय बैतूल में डॉक्टरों की टीम से पीएम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बैतूल में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतिका बबली भुसुमकर के पति की मृत्यु लगभग 4-5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और वह घर में अकेली रहती थी। इसी दौरान मृतिका के अपने ही गांव के निवासी गोलू उर्फ देवेश अतुलकर के साथ अवैध संबंध बन गए थे। 29 जून की शाम को किसी विवाद के चलते आरोपी ने लकड़ी के डंडे से मृतिका के सिर व पैर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गोलू उर्फ देवेश अतुलकर पिता तुलसीराम अतुलकर निवासी ग्राम चिखलार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त किया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हत्या के इस प्रकरण को सुलझाने में थाना प्रभारी कोतवाली रविकांत डेहरिया, निरीक्षक आबिद अंसारी, प्रभारी सीन ऑफ क्राइम, उनि पंचम सिंह उइके, उनि चित्रा कुमरे, प्र.आर. तरुण पटेल, प्र.आर. शिव कुमार, प्र.आर. सुभाष माकोड़े, आरक्षक नितिन चौहान, आरक्षक जतिराम, म.आर. सोनालीम.आर. रामरति की सराहनीय भूमिका रही।

जनकल्याण की कामना को लेकर निकली पदयात्रा पहुंची बैतूल

बैतूल। छिंदवाड़ा-पांढुर्णा सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा जनकल्याण की भावना से छिंदवाड़ा से दादाजी धूनीवाले धाम खंडवा के लिए निकाली गई पदयात्रा मंगलवार को बैतूल जिले में पहुंची है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 2 जुलाई को कान्हा भोजनालय ससुन्द्रा से यह पदयात्रा प्रारंभ होकर बैतूल पहुंचेगी। जहां बैतूल में ही रात्रि विश्राम रहेगा। 3 जुलाई को पदयात्रा बैतूल से प्रारंभ होकर प्राथमिक शाला चिखली पहुंचेंगी, यहां पदयात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। 4 जुलाई को पदयात्रा प्राथमिक शाला चिखली से प्रारंभ होकर ग्राम चिल्हौर के शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। तत्पश्चात 5 जुलाई को चिल्हौर से पदयात्रा खंडवा के लिए रवाना होगी। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा 26 जून को जनकल्याण की कामना को लेकर छिंदवाड़ा से दादाजी धूनीवाले धाम खंडवा तक की 411 किलोमीटर पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा 10 जुलाई को खंडवा धूनी वाले दादाजी के धाम पहुंचेंगी, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पदयात्रा का समापन किया जाएगा।

बैतूल को प्रदेश में मिली नई पहचान

● हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ● सत्ता हो या संगठन, हर मोर्चे पर रहे सफल

बैतूल। मध्यप्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से कई कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार आज मंगलवार को हेमंत खंडेलवाल का नाम तय हो ही गया। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष के लिए सिंगल नामांकन पत्र दाखिल हुआ और सीएम डॉ. मोहन यादव हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पहले कई नाम उछले थे, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की ही मानी जा रही थी। यहीं वजह है कि बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल निर्विरोध चुने गए, वे प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की पहली पसंद बताए जाते रहें हैं, वहीं बाकी बडे नेता भी उनके नाम पर राजी हुए। श्री खंडेलवाल के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर बैतूल को प्रदेश में नई पहचान मिली है। भाजपा की राजनीति में बैतूल जिले में विधायक हेमंत खंडेलवाल को मैनेजमेंट का गुरु माना जाता रहा है और अब भाजपा आलाकमान ने प्रदेश का नेतृत्व उनको सौंप कर यह सिद्ध भी कर दिया है। गौरतलब रहे कि बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश स्तर पर पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी।

राजनैतिक क्षेत्र का ईमानदार और परोपकारी व्यक्तित्व : हेमंत खंडेलवाल

बैतूल की राजनीति में विराट व्यक्तित्व के धनी स्व. विजय कुमार खंडेलवाल की विरासत को लेकर चल रहे पूर्व सांसद एवं वर्तमान बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल

के व्यक्तित्व में भी सेवा, समर्पण, ईमानदारी और क्षेत्र के विकास को लेकर अलग ही विजन झलकता है। राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता या व्यक्तिगत ईर्ष्या भाव में कोई उनकी राजनीति की आलोचना भले ही करें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सभी को पता है कि जरूरतमंद की मदद के मामले में हमेशा तत्पर रहते है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे मदद करने के बाद भूल जाते है, उस मदद को अपने राजनैतिक फायदे के लिए भुनाना पसंद नही करते है। हेमंत खंडेलवाल का राजनैतिक कद यह है कि प्रदेश स्तर पर पार्टी के नीति निर्धारकों में उन्हें गिना जाता है। उनकी क्षमता, कार्यकुशलता और समर्पण को देखकर ही पार्टी ने उन्हे कुशाभाऊ ठाकरे न्यास की महत्वपूर्ण जिम्मेदार सौंपी। प्रदेश की चुनाव प्रबंध समिति में वे एक बड़ी भूमिका में भी रहे। मैनेजमेंट की कला में उनका कोई सानी नहीं है। हेमंत खंडेलवाल वह व्यक्तित्व है जिन्हे प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचाना जाता है। भाजपा के अंदर उन्हे तमाम राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज व्यक्तिगत तौर पर जानते है। यह उनके राजनैतिक व्यक्तित्व को जाहिर करने वाली बातें है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वे जिस तरह से आम, गरीब लोगों की या बैतूल जिले के नागरिकों की जात, धर्म और दलगत भावना से ऊपर उठकर मदद करते है, वह बेमिसाल है। उनके विधायक कार्यकाल में स्वीकृत कराई गई विकास परियोजनाएं, सड़के, बनाए गए डेम, आज भी बैतूल के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे है। आज बतौर बैतूल विधायक भी उनके कार्यकाल में बैतूल विधानसभा में कई विकास कार्यो की सौगातें मिली है।

सत्ता हो या संगठन, हर मोर्चे पर रहे है सफल....

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद स्व. विजय कुमार खंडेलवाल के बेटे हेमंत का जन्म 3 सितंबर 1964 को यूपी के मथुरा में हुआ। उन्होंने बैतूल के जेएच गवर्नमेंट कॉलेज से 1986 में बीकॉम और 1990 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। खंडेलवाल की शादी पश्चिम बंगाल की ऋतु खंडेलवाल से हुई, उनका एक बेटा और एक बेटी है। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले हेमंत खंडेलवाल के पिताजी विजय खंडेलवाल, जो कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सांसद रहे, उनके निधन के पश्चात वर्ष 2007 के उपचुनाव में हेमंत खंडेलवाल बैतूल सीट से जीतकर सांसद बने। इसके बाद 2010 में बैतूल भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में बैतूल से विधानसभा का चुनाव जीतकर शिवराज सिंह की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश संगठन में प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बैतूल सीट से चुनाव हारने के बाद दोबारा 2024 के विधानसभा चुनाव में पुनः बैतूल से विधायक निर्वाचित हुए। वर्तमान में वे कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।

जिले में 7 जुलाई तक चलेगा फसल बीमा सप्ताह

फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

बैतूल। बैतूल जिले में खरीफ मौसम 2025 में फसलों का फसल बीमा 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जो आगामी 7 जुलाई तक चलेगा। उप संचालक कृषि आनंद कुमार बडोनिया के द्वारा 1 जुलाई को उप संचालक कृषि कार्यालय से फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही सभी तहसीलों में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों एवं कृषि विस्तार अधिकारीयो द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है एवं कृषकों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवा कर जोखिमों एवं फसल बीमा के हित लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने की इच्छुक अऋणी किसान अपनी निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत चैनल एवं जन सेवा केंद्र सीएससी एवं कृषक स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर योजना से जुड़ सकते हैं। अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज-बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बही एवं बटाईदार किसान या किराए पर ली गई भूमि के लिए मालिक द्वारा शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के किसानों से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से जुडक़र योजना का लाभ लेने की अपील की है।

जिला न्यायालय परिसर में देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बैतूल। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के पहले दिन मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर बैतूल में देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवबालक साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता भारती राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल-श्रीमती शर्मिला बिलवार, नयन जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय एवं जिले के कोरकू, माली, मेहरा, जैन, कूनबी, सरले, कुर्मी, कलार, तेली, क्षत्रिय, भोजपुरी, बंग समाज, मराठा, मांझी, कुम्हार, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यदुवंशी, रघुवंशी, सोनी आदि विभिन्न समाजों के जिला अध्यक्ष /प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा बताया गया कि समाज के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है और ऐसे प्रतिनिधि समाज के पारिवारिक व आपसी विवादों को उनके जन्म के समय ही सामाजिक स्तर पर मध्यस्थता द्वारा समाप्त करा सकते है, क्योंकि एक बार विवाद थाना या कोर्ट में आने के बाद विवाद के पक्षकार लंबे समय तक जूझते रहते है, जिससे उनका बहुमूल्य समय व धन बर्बाद होता है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा समाज के प्रतिनिधियों को 20 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इस हेतु सामाजिक संगठन द्वारा जिला या तहसील स्तर पर स्थापित सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र में ऐसे प्रशिक्षित मध्यस्थ को मध्यस्थता करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई - प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवबालक साहू द्वारा बताया गया कि परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है जब परिवार में कोई विवाद होता है, तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है इसलिये पारिवारिक विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। सामाजिक प्रतिनिधि यदि यह कार्य ईश्वरीय कार्य समझकर करे तो निश्चित रूप से उनसे गलती की संभावना नहीं रहेगी और पक्षकारों के साथ-साथ समाज के लोगों का भी उन पर विश्वास बढ़ेगा और कई मामले प्रारंभिक स्तर पर समाप्त किये जा सकेगें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा बताया गया कि पारिवारिक विवादों के संबंध में एफ.आई.आर. के पूर्व सामाजिक प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए पुलिस विभाग से आवश्यक परामर्श व सहयोग लिया जाएगा।

जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा एक दिन का वेतन

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले की सभी जनपद पंचायतों में भी प्रत्येक मंगलवार को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। सभी खंड स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में उपस्थिति संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले जिला अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उद्यानिकी, सहकारिता, खनिज, मंडी, एलडीएम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एमपीईबी इत्यादि विभागों के जिला अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं।

भूमि का कब्जा दिलाने तहसीलदार को दिए निर्देश - जनसुनवाई में शाहपुर तहसील के ग्राम चिखली रैयत निवासी साहब लाल ने भूमि का कब्जा दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि चिखली रैयत में उनकी भूमि पर रामाधार ने अवैध कब्जा कर लिया है। अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के पास से सीमांकन का केस पक्ष में आने के बाद भी मुझे मेरी भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है। आवेदक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शाहपुर तहसीलदार को तत्काल भूमि का कब्जा दिलाए जाने के निर्देश दिए। बैतूल मुख्यालय के गर्ग कॉलोनी के निवासियों ने आवेदन देकर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विद्युत उपयंत्री को निरीक्षण कर प्रकरण का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल निवासी रोशनी ने गरीबी रेखा का नया कार्ड बनाए जाने के लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

कंडम छात्रावास भवन को खाली करने के दिए निर्देश -जनसुनवाई में ग्राम पंचायत जीन निवासी सुनीता ने कंडम छात्रावास भवन खाली कराए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने ट्राइबल विभाग को छात्रावास भवन खाली करवाकर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल मुख्यालय के अर्जुन वार्ड निवासी हेमराज नागले ने आवेदन के माध्यम से राशन कार्ड बनाए जाने की मांग की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। गौठाना निवासी मंगलीबाई धुर्वे ने पुत्र के मृत्यु उपरांत शासन से मिलने वाली सहायता राशि आज दिनांक तक नहीं मिलने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण किया जाने के निर्देश दिए। ग्राम गंगापुर निवासी राजेंद्र नागले ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद पंचायत सीईओ मुलताई को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग - घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम पाढर निवासी अबरार कुरैशी ने आवेदन के माध्यम से बताया कि तहसीलदार को भूमि में नाम सुधारने के लिए पूर्व में आवेदन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए है। शाहपुर तहसील के ग्राम बरबटपुर निवासी रानी कुशवाहा ने आवासीय पट्टा दिए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल अंतर्गत ग्राम टेमनी निवासी नारायण विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद पंचायत के अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

नगरकोट के पास हाईवे पर फिर मिला दुर्लभ वन्य स्तनपाई पैंगोलिन

वन विभाग ने अंतिम संस्कार कर वरिष्ठ अधिकारी को भेजी रिपोर्ट

बैतूल/मुलताई। मुलताई क्षेत्र में एक बार फिर बैतूल रोड पर नगरकोट के पास हाईवे पर अत्यंत दुर्लभ स्तनपाई वन्य प्राणी इंडियन पैंगोलिन मृत अवस्था में मिला। मुलताई वन परिक्षेत्र अधिकारी नितिन पवार ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग अमला जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचा तब तक पैंगोलिन की मौत हो चुकी थी। मृत पैंगोलिन को वन विभाग द्वारा लाकर पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम करा कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पैंगोलिन पर चोट के निशान पाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाईवे पर किसी वाहन के चपेट में आने से जख्मी हुआ था, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि मुलताई क्षेत्र में दुर्लभ वन प्राणी पैंगोलिन के मिलने की यह तीसरी घटना है इसके पूर्व ग्राम डहुआ के सडक़ किनारे भी पैंगोलिन मिला था। पैंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची क्रमांक 1 में सूचीबद्ध है जिसे उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है। अपनी दुर्लभ बनावट और स्किल्स से बने कवच के कारण यह बहुत खास हो जाता है और यही कारण है कि दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है।

क्या मुलताई क्षेत्र में पैंगोलिन संरक्षण के होंगे प्रयास -पैंगोलिन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किंतु बार-बार मुलताई क्षेत्र में पैंगोलिन मिलने की पुष्टि के बावजूद इसके संरक्षण के प्रयास होते दिखाई नहीं दिए। संपूर्ण दुनिया में पैंगोलिन की आठ प्रजातियाँ हैं, जिनमें से चार एशिया में और चार अफ्रीका में पाई जाती हैं। दुर्भाग्य से, सभी आठ प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हैं। पैंगोलिन मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं, और उनकी लंबी, चिपचिपी जीभ उन्हें इन कीड़ों को पकडऩे में मदद करती है।

इनका कहना है - मिले हुए पैंगोलिन का पोस्टमार्टम करा कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पैंगोलिन मिलने की रिपोर्टिंग वरिष्ठ अधिकारियों को की जा रही है।

- नितिन पवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई

एक पखवाड़े की बारिश से ही डामर सड़कों की हालत खराब

सड़क पर गड्ढों के कारण वाहन चालक परेशान

बैतूल। मानूसन को आए अभी एक पखवाड़ा ही हुआ है और बैतूल शहर में मात्र 78.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, इतनी ही बारिश में सडक़ों की हालत खराब हो गई है। कई सडक़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जिस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से रात्रि के समय यह गड्ढे नजर नहीं आते और वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर रहे है। यह हाल शहर के वार्डो की सडक़ों के ही नहीं, अपितु प्रमुख चौराहों पर भी सडक़ों में गड्ढे नजर आ रहे हैं। वार्डों में सडक़ निर्माण के टेंडर लगे होने के बावजूद ठेकेदारों द्वारा समय पर निर्माण शुरू नहीं किया गया। जिसके कारण बारिश में अब वाहन चालकों के साथ राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश में सडक़ों की खस्ता हालत का मुख्य कारण पानी निकासी के इंतजाम नहीं होना हैं। जिसके कारण सडक़ पर पानी भर जाता

है। इस वजह से यह सडक़ महज छह माह ही टिकती है और इसके बाद सडक़ पर गड्ढे हो जाते हैं। हालांकि अब जितनी भी प्रमुख सडक़ें बनाई जा रही हैं उनमें नगरपालिका द्वारा नाली निर्माण भी कराया जा रह हैं, लेकिन पानी निकासी के लिए ठीक तरह से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।

गड्ढों के कारण सडक़ पर चलना मुश्किल - खस्ताहाल सडक़ से आमजनता परेशान है। बारिश में गड्ढों के कारण सडक़ पर चलना मुश्किल हो गया है। दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ गई है। लेकिन इन गड्ढों में डस्ट या मुरम डालकर समतल तक नहीं किया है। गंज क्षेत्र में व्यापारियों ने खुद गड्ढे भरे, वहीं कॉलेज चौक पर सडक़ पर बने गड्ढे वैसे ही है। इससे रोजाना वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गिट्टी ने डामर छोड़ दिया है, लेकिन अन्य विकल्प नहीं होने से लोग इसी खस्ताहाल सडक़ पर चलने को विवश हैं, जबकि इस सडक़ पर प्रतिदिन हादसे हो रहे है। कभी लोग चोटिल हो जाते है तो कभी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे है।

प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना-जाना - शहर की मुख्य सडक़ों पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। दिन में तो वाहन चालक जैसे-तैसे सडक़ के गड्ढों से बच भी जाते है, किन्तु रात्रि में गड्ढे नजर नहीं आने से कई बार वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि शहर में सडक़ों का निर्माण तो कराया जाता है, लेकिन यह सडक़ चंद सालों में ही खराब हो जाती है। जिसके बाद इनकी मरम्मत तक नहीं होगी है। मरम्मत के अभाव में सडक़ों पर बने गड्ढों का आकार बढ़ता है और सडक़ जल्द ही खराब हो जाती है। वहीं वाहन चालक सडक़ पर बने गड्ढों से बचने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल होते है। गड्ढों के वजह से वाहनों के टकराने की भी घटनाएं अक्सर सामने आती है। बार-बार वाहन गड्ढे में जाने से वाहन में टूट-फूट हो रही है। जिससे चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बारिश में डूब जाती है सडक़े - सडक़ पर पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने से बारिश के दौरान सडक़े डूब जाती है। गंज क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास बारिश में सडक़ का यहीं हाल रहता है। इसके अलावा शंकर वार्ड में फिल्टर प्लांट रोड भी पूरी तरह खराब हो चुकी है। हालांकि सडक़ का टेंडर हो चुका है। लोगों का कहना था कि पिछले साल तो डस्ट डालने से थोड़ी राहत थी, लेकिन अब पूरी सडक़ उखड़ गई है। जिससे परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज चौक पर बीच चौक पर सडक़ की हालत खस्ताहाल हो गई है। यहां भी चौक का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होना है, लेकिन इस कार्य में अभी समय लगेगा। लेकिन नपा ने बारिश के पूर्व इन गड्ढों को नहीं भरवाया गया है। जिसके कारण बारिश का पानी इन गड्ढों में थम गया है और अब आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है।

इनका कहना है -डस्ट डालकर गड्ढे भरवाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी गेंदा चौक क्षेत्र में गड्ढे भरे जा रहे है। इसके पश्चात अन्य स्थानों पर भी गड्ढे भरे जायेगे। जिससे बारिश के दौरान राहगीरों को सडक़ों पर चलने में परेशान न हो। इसके अलावा सडक़ों पर से पानी निकासी की भी व्यवस्था की जायेगी।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

संक्षिप्त समाचार

धरती आबा अभियान से जनजातीय वर्ग तक सुगमता से पहुंच रहा शासन की योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ

रायसेन (निप्र)। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय वर्ग के लोगों के पास, उनके घर पहुंचकर शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ पाकर जनजातीय वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आर्थिक उन्नति हुई है। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम डोकरी बमनई निवासी संतोष कुमार भी उन हितग्राहियों में शामिल हैं जिन्हें धरती आबा अभियान के तहत गांव में शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिया गया है। हितग्राही संतोष कुमार को धरती आबा अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, सम्बल कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, उज्जवला योजना, सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। धरती आबा अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए संतोष कुमार बताते है कि अभियान के तहत योजनाओं का लाभ मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा वह और उनका परिवार खुशहाल है।

किसानों के खेतों में डगवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण एवं खेत तालाब बने

विदिशा (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान विदिशा जिले में वृद्धि स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में दुग्वेल रिचार्ज स्ट्रक्चर और खेत तालाब का निर्माण कराया गया है किसानों के खेतों में इस तरह की संरचना स्थापित हो जाने से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी इस वर्षा ऋतु में पानी एकत्रित होता और वह किसने की फसलों में सिंचाई के लिए उपयोग होगा। किसानों के खेतों में रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण और खेत तालाब बन जाने से अब इन किसानों को सुखे की स्थिति से निपटना नहीं पड़ेगा। भूजल स्तर में सुधार होगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये संरचनाएं वर्षा के जल को भूजल में रिसने देती हैं। जिससे पानी की कमी और सूखे की समस्या की संभावना बहुत कम हो जाती है। जनपद पंचायत बासौदा की ग्राम पंचायत पैरवासा में निवासरत किसान श्री अयूब खान के खेत में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत डग्वेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का कार्य किया गया है। इसी तरह गंजबासौदा की ही ग्राम पंचायत अंबानगर के किसान श्री मनोज चिढ़ार के खेत में तालाब का निर्माण कराया गया है जो उनके कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दोनों किसानों ने जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रियान्वयन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित मकान की चाबी

सीहोर (निप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने इछावर के ग्राम कांकरखेड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की चाबी सौंपकर उनका ग्रह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक गरीब के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आवास योजना की सूची में नाम जुड़ने पर श्रीमती पार्वती देवी सहित अन्य हितग्राहितयों को बधाई पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, विधायक श्री सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, श्री रवि मालवीय, श्री विष्णु वर्मा, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

अब वर्षा जल के आभाव में भी फसलों की सिंचाई होगी आसान

■ श्री रामनिवास सांखला को मिली खेत तालाब की सौगात

हरदा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से सरकार और समाज के द्वारा पुरानी जल संरचनाओं में जल भरण, जल के प्रबंधन तथा नई जल संरचनाओं का निर्माण का कार्य जा रहा है। जल के बिना जीवन की परिकल्पना शून्य है और इसके बिना न तो कृषि संभव है, न ही उद्योग और न ही हमारी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। जल का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। हरदा जिले की जनपद पंचायत हरदा अंतर्गत ग्राम कचबैड़ी निवासी किसान रामनिवास सांखला को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नवीन खेत तालाब का उपहार मिला। खेत तालाब बनने से अब रामनिवास सांखला को वर्षा के अंतराल के दौरान फसल की सिंचाई के लिए वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेत तालाब का निर्माण होने से रामनिवास प्रफुल्लित है। रामनिवास कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नही थी कि मैं फसलों की सिंचाई या अन्य कार्य के लिए सिंचाई का साधन जुटा सकूं। खेती का कार्य पूरी तरह वर्षा जल पर निर्भर था, जिस वर्ष अच्छी नही होती थी तो उस वर्ष सिंचाई का साधन न होने के कारण फसलें सूख जाती थी। खेत तालाब का निर्माण हो जाने से अब मुझे इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

स्व-सहायता समूह से मिली नई राह, श्रीमती अंगूरी अहिरवार बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के ग्राम भटगांव की रहने वाली अंगूरी अहिरवार आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। एक समय था जब उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन आज वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। श्रीमती अंगूरी अहिरवारका जीवन बदलने की शुरुआत 18 फरवरी 2019 को हुई, जब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम में महिला समूहों के गठन का कार्य किया गया। अंगूरी अहिरवार ने साईराम स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। समूह से जुड़ने के बाद दीदी को आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने ग्राम में ही एक कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया, जिससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी बल्कि ग्रामवासियों को भी ऑनलाईन सेवाओं का लाभ मिलने लगा। अब वृद्धजनों को पेंशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बैंकिंग कार्य भी ग्राम में ही संभव हो गए हैं। इतना ही नहीं, अंगूरी अहिरवार ने मछली पालन की गतिविधि भी शुरू की जिससे उनकी आय में और वृद्धि हुई। विभिन्न संस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। वर्तमान में अंगूरी अहिरवार की मासिक आय लगभग 13,000 तक पहुंच गई है - जिसमें सीएससीसेंटर से 5,000 एवं मछली पालन से 8 हजार रुपए की आय शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन्हें 1250 रुपए मासिक सम्मान राशि भी प्राप्त हो रही है। श्रीमती अंगूरी अहिरवार बताती है कि उन्होंने अपने समूह और परिवार के सहयोग से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही हैं। अब वे अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हूं। आज श्रीमती अंगूरी न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त हुई हैं। वे समूह और ग्राम संगठन की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाकर महिलाओं को विभिन्न सामाजिक विषयों पर जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं साईराम स्व-सहायता समूह के सहयोग से अंगूरी अहिरवार ने जो सफलता प्राप्त की है, वह निश्चित ही अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण है।

न्याय संवाद एक नई पहल के तहत जिला न्यायालय में सत्र आयोजित

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार सीहोर जिला न्यायालय परिसर में स्थित अधिवक्ता संघ के सभाकक्ष में न्याय संवाद एक नई पहल के तहत सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही न्याय संवाद के अंतर्गत होने वाली अनौपचारिक चर्चा को उल्लेखनीय पहल बताते हुये युवा अधिवक्ताओं के लिए पहल को अत्यधिक लाभकारी बताया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी ने स्थायी लोक अदालत लोकोपयोगी विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने पीड़ित प्रतिकर योजना एवं न्याय संवाद एक नई पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत प्रतिमाह अधिवक्तागण एव न्यायाधीशगण मिलकर नियत कानूनी विषय पर उसके प्रावधानों, कठिनाईयो तथा समाधानों पर विस्तार से चर्चा करते है, जो कि सभी के लिए लाभकारी है और पक्षकारों को भी इससे फायदा हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री राधेश्याम यादव, अभिभाषक संघ सचिव श्री राजेश वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान सहित अन्य अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, अधिवक्तागण लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स उपस्थित थे।

खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही: मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर किए जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग को खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने के दिशा-निर्देश दिए थे। इसी अनुक्रम में खनिज विभाग द्वारा शनिवार को मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर तथा ग्राम चापड़ा रैयत में खनिज रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज अमला द्वारा 28 जून को तहसील बैतूल अन्तर्गत आठनेर रोड पर ग्राम सूरगांव के समीप 4 डम्पर क्रमशः बीआर 31 जीए 3604, एमपी 04 एचई 5410, एमएच 12 डब्ल्यूजे 9371 एवं एमएच 12 डब्ल्यूजे 9471 को खनिज मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।

भौंरा रेत खदान से बिना अनुमति के भंडारित की गई थी रेत : इसी प्रकार खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर तहसील शाहपुर ग्राम चापड़ा रैयत स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 6/2/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर निर्माणाधीन होटल के पीछे खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाये जाने पर अवैध भण्डारणकर्ता पर कार्यवाही की गई। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खनिज रेत को भौंरा रेत खदान से ट्रेक्टर-ट्रालियों से परिवहन करके बिना अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित की गई थी, जिसकी कुल मात्रा 180 घन मीटर पाई गई। मौके पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा उक्त खनिज रेत के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनुमति एवं रॉयल्टी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

मौके पर सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा प्रभारी खनि सर्वयर, हल्का पटवारी एवं अन्य पंचगणों की उपस्थिति में पंचनामा, जप्ती पत्रक तैयार कर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है, कि खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के निर्देशन में लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उक्त सभी अवैध परिवहनकर्ताओं एवं भण्डारणकर्ता के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड प्रस्तावित कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

उमरवानी के कृषक अर्जुन ने रोटावेटर से खेती को बनाया लाभ का व्यवसाय

नरवाई जलाने की जगह अपनाई तकनीक, बढ़ी मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता

बैतूल (निप्र)। यदि इच्छाशक्ति हो और सरकार की योजनाओं का सही उपयोग किया जाए, तो खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। बैतूल जिले के ग्राम उमरवानी के किसान श्री अर्जुन धुर्वे ने कृषि यंत्रीकरण की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम उठाते हुए आधुनिक खेती को अपनाया है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने एक लाख रुपये मूल्य का रोटावेटर खरीदा, जिसमें उन्हें 46 हजार 800 रुपये का अनुदान मिला।

यह उपकरण अब उनकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल रहा है। रोटावेटर के माध्यम से कृषक श्री धुर्वे अब गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची नरवाई को जलाने के बजाय उसे बारीकी से काटकर मिट्टी में मिला देते हैं। इस तकनीक से न सिर्फ खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी सकारात्मक सुधार देखा गया है।

अन्य किसानों के लिए भी बने मिसाल

कृषि विभाग के अधिकारियों ने श्री धुर्वे की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अनुदान योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आधुनिक उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे खेती में लागत घटे और लाभ बढ़े। कृषक श्री धुर्वे ने बताया कि पहले हम नरवाई को जलाने के लिए मजबूर थे, जिससे न केवल मिट्टी की सेहत बिगड़ती थी, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता था। अब रोटावेटर से वही नरवाई मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक खाद बन जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है और लागत भी कम आती है। जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

अभी तक किया जा चुका है 5358 हितग्राहियों को लाभान्वित

धरती आबा अभियान के तहत शिविर लगाकर किया गया 179 हितग्राहियों को लाभान्वित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक-आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति के उद्देश्य से जिले में 15 जून से 15 जुलाई तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सीहोर जिले के चिन्हित 80 गांवों में अब 15 जुलाई तक दिनांकवार शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत ग्रामों में ग्राम सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत 29 जून को चिन्हित गांवों में शिविर लगाकर 179 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

अभियान के तहत जिले के चिन्हित गांवों में लगाए जा रहे शिविरों में अभी तक 5358 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए सीहोर जिले के 80 गांवों के जनजातीय समुदाय के नागरिकों से अभियान के तहत दिनांकवार लगने वाले शिविरों में उपस्थित होने और योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि सभी पात्र हितग्राही शिविरों में उपस्थित हों और पात्रतानुसार शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ लें, ताकि

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का भी निरंतर विकास हो सके और कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। शिविरों में हितग्राहियों का आयुष्मान भारत योजना, केसीसी योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मातृवंदना योजना, बाल आर्शीवाद योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं बोनस योजना, एकलव्य योजना, दिव्यांग पेंशन प्रोत्साहन योजना, कल्याणी पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्यघर योजना, घरेलू कनेक्शन सब्सीडी योजना, पांच रूपये में नवीन विद्युत कनेक्शन योजना, पीएम आवास योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए पंजीयन किया जा रहा है और इन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान के तहत सभी पात्र हितग्राहियों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, ई-केवायसी, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रोफाइल पंजीयन एवं बैंक खाता खोलना सहित अनेक सेवाओं के लिए पंजीयन भी किया जा रहा है।

जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों को उर्वरक मिलने में परेशानी न हो : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल (निप्र)। खरीफ सीजन में बुवाई के लिए जिले में खाद की उपलब्धता पर्याप्त हैं। किसानों को उर्वरक मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने उप संचालक कृषि सहित सभी एसडीओ कृषि, आरएईओ और एसीटीओ को दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण की ब्लॉकवार विस्तार से समीक्षा की। उपसंचालक कृषि ने जानकारी दते हुए बताया की जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में 8000 मीट्रिक टन उर्वरक जिले में उपलब्ध हैं। 30 जून तक जिले को एक और उर्वरक की रैक प्राप्त होगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीओ अपने क्षेत्र में समितियां और निजी खाद की दुकानों का निरीक्षण कर स्टॉक वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराएं। खाद का निर्धारित दर से अधिक विक्रय करने वाले या अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएं। उन्होंने कहा कि जिन समितियों और खाद की दुकानों में उर्वरक की उपलब्धता है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में सभी एसडीओ कृषि से खाद की उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। साथ ही निजी दुकानों और समितियों के उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में पाई गई कमियों के बारे में भी पूछा। उन्होंने संतोष जनक जवाब नहीं देने और भैंसदेही में खाद वितरण के लिए उचित कदम नहीं उठाने पर एसडीओ कृषि भैंसदेही की एक वेतन वृद्धि रोके जाने का कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

प्रधान जिला न्यायाधीश सहित न्यायाधीश गणों और अधिकारियों ने किया पौधारोपण

सीहोर (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पंच-ज योजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम अलादाखेड़ी इछावर रोड पर प्रस्तावित नवीन

पौधरोपण कार्यक्रम में रोपे गए लगभग 500 पौधे

जिला न्यायालय भवन सीहोर की रिक्त भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य एवं अन्य न्यायाधीशगणों में ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। वर्तमान में मानव द्वारा पेड़ों का अत्यधिक दोहन किया गया है जिस कारण मानव जीवन पर जलवायु परिवर्तन का संकट मंडराने लगा है।

हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। कार्यक्रम में न्यायालय के सभी न्यायाधीशगणों, अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा कर्मचारीगण द्वारा लगभग 500 पौधे रोपे गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए हैं ताकि पौधों की देखभाल भी सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मण्डलोई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश श्री संजय गोयल, जिला न्यायाधीश श्री एमके वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायाधीश श्री दीपेंद्र मालू, जिला वन मंडल अधिकारी श्री मगन सिंह डाबर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राधेश्याम यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, न्यायालय अधीक्षक सपना शर्मा, लीड बैंक मैनेजर श्री जयदीप भट्टाचार्य सहित जन अभियान परिषद, युवा विकास मंडल, समर्थन एनजीओ के प्रतिनिधिगण , सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्तागण लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पैरालीगल वालेन्टियर्स ने भी पौधारोपण किया।

तीन किसानों को पीएमकेएसवाय योजना में स्प्रिंकलर सिस्टम प्रदान किये

विदिशा (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में जल स्रोतों को संवारने के साथ-साथ पानी की बचत करने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा भी गतिविधियां आयोजित की गईं और कृषकों को फसल में पानी छिड़काव के लिए पीएमकेएसवाय के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम प्रदान किए गए हैं, जिसमें विदिशा जिले के ग्राम गढ़ला निवासी किसान श्री सरदार सिंह, ग्राम शेरपुर निवासी श्री समीर खान और ग्राम सहजाखेड़ी के समीर खान लाभान्वित हुए हैं। इन तीनों किसानों को कृषि विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम प्रदान किए गए हैं किसानों का कहना है कि यह सिस्टम प्रणाली के माध्यम से उनके खेतों में वह पानी का छिड़काव कर सकेंगे जो उनके लिए उपयोगी साबित होगा।

'एक बगिया मां के नाम' बनेगी आजीविका का नया माध्यम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा–प्रदेश की महिलाएं होंगी लाभान्वित

- सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समितियों का होगा गठन
- राज्य सरकार 7 से 6 अगस्त तक करेगी मूंग व उड़द का उपार्जन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 'एक बगिया मां के नाम' से नई योजना आरंभ की जा रही है। इसमें प्रदेश स्तर पर स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे। इस योजना में हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग और सिंचाई के लिए जल कुंड बनाने के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। उद्यान विकास के लिए महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-10 एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान आयोजित होगा, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, वन, उद्यानिकी सहित सभी विभाग जनसहभागिता से संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाना है। समिति में सांसद, विधायक, पंचायत तथा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी डेयरी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रख्यातजन शामिल होंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान में बने 85 हजार से अधिक खेत तालाब

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खेत का पानी खेत में संचित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 85 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया। भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण किया गया। पानी की अमृत बूंद को सहेजने के लिए अमृत सरोवर 2.0 के तहत 1000 से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र में समाज की सहभागिता से 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई और 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई। इसके साथ ही 40 लाख से अधिक नागरिकों ने 5000 से अधिक ऐतिहासिक/धार्मिक जल स्रोतों (बावड़ी, मंदिर तालाबों आदि) की सफाई और जीर्णोद्धार में भाग लिया। अभियान के अंतर्गत 2 लाख 30 हजार जलदूतों का रजिस्ट्रेशन हुआ।

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुईं 15 हजार से अधिक जल संरचनाएं

नर्मदा पक्रिमा पथ और पंचकोषी यात्रा जैसे अन्य तीर्थ मार्गों का डिजिटलीकरण किया गया। अवरिल निर्मल नर्मदा योजना के तहत 5600 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण की योजना स्वीकृत कराकर कार्य आरंभ किया गया। वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम जैसी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रदेश की 15 हजार से अधिक जल संरचनाओं और जल संग्रहण संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य भी अभियान के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मानसून में रोपण के लिए 6 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार किसानों ने तथा उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन हो चुका है। पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक अंतिम तिथि निर्धारित है। प्रदेशभर में मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन 30 जून को पूर्ण कर लिया गया है, इससे प्रदेश को 40 साल पुराने इस कलंक से मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रतलाम में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एंप्लॉयमेंट कॉन्क्लेव (RISE) तथा गुजरात के सूरत में आयोजित निवेशक संवाद कार्यक्रम की उपलब्धियों से मंत्रीगण को अवगत कराया।

एमपी के 75 छात्रों के लिए दोबारा होगी नीट-यूजी परीक्षा

इंदौर हाईकोर्ट का एनटीए को आदेश, एग्जाम सेंटरों पर बिजली गुल हुई थी

भोपाल। इंदौर के 75 स्टूडेंट के लिए दोबारा NEET-UG की परीक्षा कराई जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को दोबारा परीक्षा कराने और जल्द रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की रैंक केवल उसके फिर से होने वाली परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही मानी जाएगी। दरअसल, 4 मई को परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई

एग्जाम सेंटर की बिजली गुल हो गई थी। छात्रों ने अदालत से कहा था कि बिजली गुल होने से परीक्षा पर असर पड़ा। जिन छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है, उन्होंने 3 जून से पहले याचिका दाखिल की थी। यह परीक्षा केवल उन 75 छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी, जिन्होंने 3 जून के पहले याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट के जज ने कोर्ट रूम बिजली बंद कराकर परीक्षा पेपर पढ़ा था। जज ने ऐसा इसलिए किया ताकि उस वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगा सकें, जिसमें छात्रों को परीक्षा देनी पड़ी। आज दिए आदेश में कोर्ट ने कहा, परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती न होने के बावजूद, उन्हें बिजली कटौती के कारण असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया गया था।

सरकारी नौकरी पाने की खुशी चेहरों पर आई नजर

एमपी ट्रांसको में चयनित अभ्यर्थियों ने कराए दस्तावेजों के भौतिक परीक्षण

भोपाल। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के भौतिक परीक्षण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई। शासकीय सेवा में नियुक्ति का सपना साकार होने की संतुष्टि और उल्लास चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर साफ झलक रहा था। पहले दिन कुल 22

अभ्यर्थियों ने आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ दस्तावेज परीक्षण में भाग लिया। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी नियत समय पर आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित हुए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षण संपन्न कराया। दस्तावेज परीक्षण की यह प्रक्रिया आगामी 3 जुलाई तक प्रतिदिन जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दस्तावेज परीक्षण के पहले दिन कनिष्ठ अभियंता (पारेषण-प्रशिक्षु) एवं सिविल लाइन परिचारक (प्रशिक्षु) पदों के लिए चयनित 22 अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों का परीक्षण कराया। उन्होंने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिससे चयनित अभ्यर्थी समय पर विभाग की सेवा में योगदान दे सकें।

जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश सलमान अहमद गिरफ्तार

हाल ही में अजमेर से लौटा, हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में था फरार

भोपाल। भोपाल की अपराध शाखा और थाना मंगलवारा पुलिस ने अपराधी सलमान अहमद उर्फ एमआईजी को सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एक अवैध धारदार चाकू भी बरामद किया है। सलमान हाल ही में अजमेर से वापस लौटा था और भोपाल में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। सोमवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक नगर निगम की पानी की टंकी के पास खड़ा है। सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर टीम ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सलमान

अहमद उर्फ एमआईजी (33) बताया। साथ ही कहा कि वह करोंद की विवेकानंद कॉलोनी में रहता है। तलाशी में उसकी कमर में टी-शर्ट के अंदर छिपाकर रखा गया चाकू बरामद हुआ है। चाकू पर खाकी रंग का पुठ्ठे का कवर चढ़ा था। चाकू के अवैध होने की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ थाना मंगलवारा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी सलमान हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना के साथ शामिल था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। सलमान ने बताया कि वह अजमेर भाग गया था। कुछ दिन पहले ही भोपाल लौटा था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज हैं।

एमपी में अंगदान-देहदान करने वालों को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर

परिवार का भी होगा साल में दो बार सम्मान, सरकार ने जारी किए आदेश

भोपाल। अब मध्यप्रदेश में अंगदान और देहदान करने वालों का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाएगा। इसकी घोषणा फरवरी माह में AIIMS में हुए पहले हृदय प्रत्यारोपण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ने किया था। जिसका पालन करते हुए मंगलवार को मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। AIIMS के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में हृदय प्रत्यारोपण और अन्य अंग प्रत्यारोपण की सुविधा को मजबूत किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस की सुविधा हर उस जगह है। जहां पर इसको पहुंचाया जा सकता है। जहां एयर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। वहां हेलिकॉप्टर की सुविधा दी जा रही है। जिससे मरीजों को समय से उपचार मुहैया कराया जा सके। उन्होंने अपील भी की कि अंगदान और देहदान को सभी प्राथमिकता दें। ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को नया जीवन मिलेगा। अब देहदान करने वाले या हृदय, लिवर, गुर्दे जैसे अंगों का दान करने वाले नागरिकों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों,

पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए हैं। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों से इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में साफ किया गया है कि इस पहल का उद्देश्य अंगदान और देहदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। इन महान दानदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। दानदाताओं के परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने की भी घोषणा की गई थी। इसके साथ सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान व अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार करने की भी योजना तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। देहदान और अंगदान जीवन का सबसे महान दान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह निर्णय निश्चित ही अधिक से अधिक लोगों को अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करेगा। इसके माध्यम से अनेक लोगों को नया जीवन प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश सरकार ने अंगदान और देहदान करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के साथ उनके परिजन को भी सम्मानित करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब हर साल में दो बार परिवार का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए लोकल अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 26 जनवरी और 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों में अंगदान और देहदान करने वालों के परिवार को सम्मानित करें। नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में कुल 1,099 कैडेवर डोनेशन हुए थे। इनमें से तेलंगाना में सर्वाधिक 252 डोनेशन हुए, जबकि मध्य प्रदेश में यह संख्या मात्र 8 रही। एम्स भोपाल की यह सफलता निश्चित रूप से प्रदेश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

एमपी में जानलेवा स्मार्ट मीटर! बिल देखते ही बिगड़ी तबीयत

गरीब आदमी को आया 70 लाख का बिजली बिल, देखते ही लगा शॉक

भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 65 साल के एक व्यक्ति को 69.75 लाख रुपए का बिजली बिल मिला है। बिल देखकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शहर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई लोगों को ऐसे ही भारी-भरकम बिल मिले हैं। बिजली विभाग का कहना है कि बिलिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। सरकार ने स्मार्ट मीटर सही बिलिंग के लिए लगाए थे, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बन गए हैं। होम गार्ड रोड पर रहने वाले मुरारीलाल तिवारी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वे बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनके स्मार्ट मीटर में सिर्फ 219 यूनिट बिजली इस्तेमाल होना दिखा। फिर भी, पिछले महीने का बिल 69 लाख रुपए से ज्यादा आया। तिवारी जी ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा, उनके अगले बिल में 1 लाख रुपए का जुर्माना और जोड़ दिया गया। वहीं, तिवारी जी के पड़ोसी, महेंद्र सिंह रघुवंशी को भी 68 लाख रुपए का बिल मिला है। गरीब बस्तियों, जैसे कि आग्या राम कॉलोनी में भी कई मजदूरों को लाखों रुपए के बिल मिले हैं। पहले वे हर महीने सिर्फ 100 से 200 रुपए का बिल भरते थे। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर बिना बताए और बिना पूछे लगा दिए गए। बिजली विभाग और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिलिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण बिल ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 15 मामलों में बिल गलत पाए गए हैं। स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजना के तहत लगाए गए थे। इसका मकसद था कि बिजली का बिल सही और पारदर्शी हो। मुरारीलाल तिवारी ने बताया कि बिल देखने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी हालत देखकर उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए। तिवारी जी ने कहा कि इतना बिल देखकर तो किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार को तुरंत इस मामले में ध्यान देना चाहिए। लोगों की मांग है कि गलत बिलों को ठीक किया जाए और स्मार्ट मीटर लगाने से पहले लोगों को जानकारी दी जाए।

भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश

प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना फूटा, श्योपुर में क्वारी नदी उफनी; 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहा। भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश हुई। वहीं, बालाघाट में सबसे ज्यादा पौने 2 इंच पानी बरस गया। सीधी में सवा इंच, श्योपुर-सिवनी में 1 इंच, बैतूल, शिवपुरी-मंडला में पौन इंच और पचमढ़ी, छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर में आधा इंच पानी गिरा।

दतिया, गुना, नर्मदापुरम, छतरपुर, रायसेन, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, उमरिया, मऊगंज, शाजापुर, आगर-मालवा, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना बहुती जलप्रपात में पानी आ गया है। ये झरना मऊगंज जिले में है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। यहां पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। श्योपुर जिले में सुबह से बारिश का दौर जारी बना हुआ है। लगातार बारिश से विजयपुर में क्वारी नदी उफान पर है। इससे निचली बस्तियों में पानी भरने का खतरा है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि मध्यप्रदेश के ऊपर से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। वहीं, एक अन्य टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का भी असर है। इनकी वजह से प्रदेश में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

श्योपुर में पुलिया पर से बह रहा क्वारी नदी का पानी- श्योपुर में विजयपुर से अगरा जाने वाली रास्ते में इकलौद की पुलिया पर क्वारी नदी का पानी आ गया है, जिससे

मार्ग बंद हो गया है। इससे अगरा, अरोंद, बेनीपुरा, बरोदा, धामनी सहित कई गांव का संपर्क टूट गया है।

इन जिलों में आज गिरेगा पानी- मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। श्योपुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना, सीधी में भारी बारिश का अलर्ट है।

एमपी का सबसे ऊंचा झरना बह निकला- मध्यप्रदेश का सबसे ऊंचा झरना बहुती जलप्रपात में पानी आ गया है। ये झरना मऊगंज जिले में है। यहां पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं।